1. Notification No. 82/2004-Customs, dated the 18 August, 2004, seeking to amend Notification No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 so as to reduce effective rates of customs duty on petrol, diesel, kerosene (for PDS) and LPG with effect from the 18th August, 2004, under section 159 of the Customs Act, 1962.

2. Notification No. 44/2004-Central Excise, dated the 18th August, 2004, seeking to amend Notification No. 6/2002-Central Excise dated the 1st March, 2002, so as to reduce effective rate of excise duty on petrol, diesel and kerosene (for PDS) with effect from the 18th August, 2004, under sub section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944. [Placed in Library. For (1) and (2) *see* No.LT.724/04]

SHORT DURATION DISCUSSION

Due to changes made in School Textbooks by Central Government

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up the short duration discussion on the situation arising due to changes in the school textbooks by the Central Government. Dr. Murli Manohar Joshi will initiate the discussion.

डा. मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश) **:** उपसभापति जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने का निर्णय लिया हैं और इस पर चर्चा के लिए जो मुझे समय दिया हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।पिछले दो-तीन महीनों में सरकार के द्वारा जिस प्रकार के पाठ्य-पुस्तकों में मनमाने ढंग से फेर-बदल करके छात्रो, अध्यापकों और अभिभावकों को बड़ी भारी कठिनाई में डालने का काम शुरू किया हैं, उससे देश के सामने और विशेषकर के छात्रों के सामने, अध्यापको के सामने बहुत बड़ी कठिनाइयां पैदा हुई हैं, बहुत से कन्फ्यूजन पैदा हुए हैं और इस बात को लेकर सारे देश में बहुत चिंता हैं।

उपसभापति महोदय, मेरे सामने सरकार का एक आदेश हैं, जो इन्होने 12 जून को प्रसारित किया था। उस आदेश में इन्होने यह कहा है"The issues of communalisation and inadequacies of history textbooks of the NCERT have engaged public and academic attention for a long time." मैं नहीं जानता कि कौन सी शिकायतें किन किताबों के बारे में सरकार के पास आई। जब ये किताबें छपी थीं और जब यह पाठ्यक्रम बनाया जा रहा था तो उसके बाद किसी ने भी, न भी, न तो किसी मुस्लिम संस्था ने, न किसी ईसाई संस्था ने, न किसी सिख संस्था ने, न किसी यहूदी संस्था ने और न किसी संप्रदाय या किसी भी धर्म को मानने वालों ने कोई शिकायत की थी कि इन पुस्तको में सांप्रदायिक या किसी भी धर्म को मानने वालों में कोई शिकयत की थी कि इन पुस्तकों में सांप्रदायिक भेदभाव हैं या सांप्रदायिकता हैं। सरकार ने उस समय यह कहा था, उस समय मैं मंत्रालय में था, कि अगर कोई भी बात इन पाठ्य-पुस्तकों मे आपत्तिजनक होगी, संविधान के खिलाफ होगी,हमारी सरकार की सेकुलरिज्म की मान्यताओं के खिलाफ होगी तो उसके बारे में हमें बताया जाए, हम उसे सुधारेंगे, लेकिन कोई भी शिकयत कहीं से भी नहीं आई। फिर भी सरकार ने एक राजनैतिक फैसला लिया।

उसके कोई कारण नहीं बताए कि कौन सी शिकायत आई। एक कमेटी बनाई गई। किस काम के लिए? यह कि पहले तो वह देखे "If they so recommend, the Government will direct the NCERT क्या रिकमंड करे? वह कहते हैं "Even as the processes are initiated to address the long-term remedial measures, including reconstitution of the Central Advisory Board of Education, and the initiation of the process of curriculum framework review, as a short-term measure, it has been considered necessary to do a quick review of these books by a panel of eminent historians."

उनकी टर्म्स और कंडीशंस क्या थी, पहली "For removing distorted and communally biased portions." दूसरी"For inclusion of short passages which will fill in the gaps that some of these books are supposed to be having or could develop after the removal of the aforesaid mentioned passages."

कमेटी में तीन महानुभाव रखे गए। प्रो.एस.सत्तार, प्रो.जे.एस.ग्रेवाल और प्रो. वरूण देव। इनमे से श्री सत्तार आई.एच.सी. –इंडियन हिस्टोरिकल कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं और श्री वरूण देव और श्री ग्रेवाल पहले अध्यक्ष रहे हैं और यह वहीं आई.एच.सी. हैं, जिसने बहुत सारी त्रुटिंया इन किताबों के अंदर दिखाई थी,जिसका जवाब अच्छी तरह से दिया गया था, सदन में यहां भी दिया जा चुका था, बाहर भी दिया जा चुका था। लेकिन यह एक विशेष प्रकार के लोगों को, जिसमें प्रो. वरूण देव के बारे में मुझे बताया गया हैं कि वे साम्यवादी पार्टी से संबंधित रहे हैं, उनको रखा गया और वे दो लोग भी हैं जो पुराने आई.एच.सी. के अध्यक्ष रहे हैं जो बराबर बहुत सी ऐसी बातों को कहतें रहे हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी। लेकिन फिर भी उनको रखा गया और उन्हीं लोगों को यह काम दिया गया कि वे रिपोर्ट करें। अब आप देखिए कि सत्तार साहब ने और वरूण देव साहब ने जो चिट्ठीयां लिखी हैं उसमें कोई कहीं गलती किताबों में नहीं बताई गई हैं और कहीं कोई साम्प्रदायिकता नहीं दिखाई गई हैं। जो रिकमंडेशंस हैं उनका संक्षेप यह हैं

प्रो. सत्तार साहब की रिकमंडेशन हैं"The relevant specialists at the NCERT may be entrusted with the task of searching out alternative reading material available in the market as well in their own institutions which may be reviewed by the panel. The specialists of NCERT may prepare a tentative advisory on the current texts which could be worked upon by the panel." इन्होने किसी दूसरी किताब की सिफारिश नहीं की, यानी इस किताब के बारे में या तो उन्होने पढ़ा नहीं और अगर पढ़ा नहीं और अगर पढ़ा हैं तो इन्हें फिर किसी प्रकार की त्रुटि या उसमें कोई कम्युनलाइजेशन आस्पेक्ट या किसी प्रकार के डिस्टॉर्शन नजर नहीं आए, उन्होने सीधे यह कहा कि जो मेटीरियल मार्केट में अवेलेबल है उसको देखकर आप टेंटेटिव एडवाइजरी बना दें उनके लिए।

वरूण देव साहब ने "In view of the exigency, the NCERT may consider reprinting only for this year the book on 'Modern India' for Class 12th by Bipin Chandra with minor updating if considered necessary."

प्रों. वरूण देव और श्री विपिन चन्द्रा कुछ किताबों के ऑथर रह चुके हैं, यानी पुराने संबंध हैं। मुझे देनी हैं किताब, मुझे कुछ बताना हैं तो मैने विपिन चन्द्रा को बतला दिया, क्योंकि मैं उनके साथ किताब लिखता रहा हूं। हो सकता हैं कि कुछ नई किताब लिखी जाए तो फिर कुछ लिखने को मिल जाएगा। प्रो. ग्रेवाल ने कहा कि There is only one alternative reading "Medieval India" by Satish Chandra, NCERT. An advisory on this sort of book may be prepared in consultation with the panel and circulated amongst teachers and students"

विपिन चन्द्रा साहब के साथ ग्रेवाल साहब भी को-आथर रहे चुके हैं और दोनो में अध्यापक और शिष्य का संबंध रहा हैं। इसलिए जो कमेटी बनाई,उसके राजनीतिक और एक प्रकार के, जिसको कहना चाहिए, पूर्व नियोजित उद्देश्य बहुत सामने हैं। उन्होने कोई गलती कम्सुनलाइजेशन के बारे में नहीं बताई। इनका ब्रीफ था कि यह बतलाते कि उसमें कम्युनलाइलजेशन कहां हैं, उसमें सेफ्रनाइजेशन कहां हैं, वह टॉक्सिन कहां हैं जिसको डी-टोक्सिफाइ करने की बात कहीं जा रही हैं। एक शब्द उसके बारे में नहीं हैं। मैने इनकी रिपोर्ट को भी पढ़ा हैं और फिर मैने उसके बाद यह भी देखा कि उस रिपोर्ट के आधार पर जो एक पुस्तके हैंक, उनको देखने पर बहुत हास्यास्पद बातें नजर आती हैं। पहली बात यह हैं कि उन्होने एक पुस्तक जोMedieval India by Meenakshi Jain की हैं उसके बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं और ज्यादातर टिप्पणिण्यां की हैं और ज्यादातर टिप्पणियां वहीं हैं, जो आई.एच.सी. की किताब में पहले छप चुका हैं और जिनका जवाब दिया जा चुका था। उसमें यह बात कहीं गई हैं कि ग्रेवाल साहब को इसके बारे में आपत्ति हैं कि He cites the index of errors which states, आई एच.सी. ने छापी थी।

It states, "Kabir appears very briefly in this book. Only one sentence is devoted to him.* Now, the author says, आप आथर की किताब में देखिये कि क्या हैं। अगर आप पेज 125, 126 पर देखे तो लिखा हैं "an important group of *sants* flourished in the Hindi-speaking North, between the 14th and 18th centuries, devoted to the Nirguna, an attribute-less divinity. Among them was the weaver, Kabir, often regarded as an apostle of Hindu-Muslim unity, born in Banaras and brought up in a Muslim family, probably towards the end of the 15th century. Kabir was opposed to all forms of orthodoxy, whether associated with the mosque or temple. His works composed in an old Hindi dialect, are found in the Adigranth, the Panchvani and the Bijak. Kabir is considered the spiritual preceptor of all subsequent North Indian *sants*. इतना डिटेल में लिखने के बावजूद, आब्जेक्शन क्या दिया जा रहा हैं?Kabir appears very briefly in this book.'

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) in the Chair.]

ऐसे ही सारे आब्जेक्शन्स हैं। मैं इनके बारे में ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसके बारे में एक और उदाहरण देकर मैं मिडिल हिस्टरी को समाप्त करूंगा। 'Professor Grewal thinks that Emperor Akbar's prohibition of the slave trade is not mentioned in the textbook. The author says - on page 200, it is clearly stated- "In 1562,

Akbar forbade the then prevalent practice of his troops keeping or selling the wives and children of rebels. However, the prohibition proved impossible to enforce. Akbar's conquests ensured the slave trade a steady supply." अर्थात स्लेव ट्रेड के बारे में पूरा डिसकशन हैं और जो सहीं बाते हैं, वे इसमें लिखी गयी हैं। वे स्पेसिफिक हैं। अब आप यह कह सकते हैं कि तारीख वगैरह ठीक हैं या नहीं या अकबर ने कांकेस्ट में आर्डर दिया था या नहीं दिया था, ऐसी कोई बात होती, तो हमारी समझ मे आता कि ये बातें कहीं जा रही हैं।

फिर कहा गया हैं कि 'Professor Grewal objects to the claim that the awesome military apparatus of the Mughal State was meant to recapture and re-conquer restive people and territories. He counters that the Army was intended to provide security against foreign invasions. Professor Grewal is unable to substantiate which foreign powers or adventurers threatened India in the Mughal times.' उसका कहीं उदाहरण नहीं हैं कि भारत पर किसी ने ऐसे आक्रमण किये हों। मेरा कहना एक किताब के बारे में यह हैं।

दूसरी किताब के बारे में भी बहुत ही मजेदार बाते हैं, त्रुटिंया दिखाई गई हैं जिसके आधार पर ये आदेश निकाले गये हैं, वे बहुत ही हास्यास्पद हैं। जैसे यह कहा गया हैं, जिस पर आपत्ति की गई हैं कि इसे किताब में से हटा दीजिए। मैं इसको कोट कर रहा हूं। "Have you ever thought how human beings lived on earth in ancient times?" अब जिस हिस्से को हटाये जाने के लिए कहा हैं, वह यह हैं"At that time, there were no televisions or radio, no railways or buses or cars. For a long time, humans didn't know how to read or write. But how do we know about people who lived such a long time ago अब इसमें से यहां हटा दीजिए", 'At that time, there were no televisions or radio, no buses or cars' क्या यह तथ्यों के विपरीत हैं? क्या यह साम्प्रदायिक भावना फैला रहा हैं? क्या बात हैं जो इसको हटाने के लिए कहा जा रहा हें। इसमें ऐसी त्रुटियां दी गई हैं।

एक जगह लिखा गया हैं"The old Iranian culture and religion were similar to those of the Vedic people. The names of Gods and various rituals were similar. This ancient religion was called Zoroastrianism." कहते हैं हटाओं किसे for, "about which you will learn in detail in the lesson on 'Religions of people in India." इसको हटा दो। यह लिखा हुआ हैं "you will learn in detail." हमने तो सर्व-धर्म-सम्भाव को पाठ्यक्रम में पढने की व्यवस्था रखी हैं। दुनिया के जितने धर्म हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ाना चाहते हैं।Zoroastriasism के बारे में हम पढ़ाना चाहते हैं और अच्छी तरह से पढ़ायेंगे। इस्लाम के बारे में भी जानकारी देंगे। इसाईयत के बारे मे भी जानकारी देंगे, बौद्धिज्म के बारे मे भी जानकारी देंगे, जैनिज्म, सिखिज्म के बारे में, यहूदियों के बारे में, सबके बारे में जानकारी देंगे। यह हमारे पाठ्यक्रम में हैं। सर्व-धर्म-सम्भाव होना ही चाहिए। अब कहते हैं कि इसको हटा दों। ये कैसे एमिनेंट हिस्टोरियन हैं, यह मुझे पता नहीं हैं। और भी मजेदार बातें इसमें कहीं गई हैं।

एक बात यह कहीं गयी हैं "Chandragupta Maurya was the first King who brought almost the whole of India under one political authority. The credit for this unification of the country is rightly given to Chanakya. He was the teacher of Arthashastra in Taxila, which was a famous centre of learning in those days."

अब कहते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ को हटा दो। इसमे क्या आपत्ति हैं? चन्द्रगुप्त ने क्या किया। उसने देश में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, देश को एक झंडे के नीचे लाने की कोशिश की। इसको हटा दो, क्यों? इसलिए कि कोई तर्क नहीं हैं।

एक और बहुत ही आनन्ददायक बात कहीं जा रही हैं। एक किताब में लिखा हैं कि The Satavahanas established a number of Budhist Monasteries. Budhist temples called Chaityas and Monasteries called Viharas were built. The most famous Chityas are those at Karle and Bhaje in Pune, Maharashtra. कहते हैं कि "पुणे, महाराष्ट्र" को हटा दो। क्यों? पुणे और महाराष्ट्र से आपको क्या आपत्ति हैं? कहां लिखें कि वह चैत्य कहां हैं? टिम्बकटू में लिखे, कि यहां नहीं हैं, वहां है? इस तरह की जो किताबों में गलतियां निकाली जा रही हैं और इनको हटाने की बात कही जा रही हैं और कहा जा रहा हैं कि वे हैं जो इरेंलेवेंट चीजें हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये इरेंलेवेंट कैसे हो सकती हैं। फिर कहा जाता हैं कि किताबों में कुछ इमोश्नल चीजे हैं, उन्हें हटा दो। क्या इमोश्नल चीजें हैंThe earth was regarded as a mother who feeds and sustains the lives of her children. Therefore, she must be regardedकहते हैं, इसको हटा दो। मातृभूमि की इज्जत न करे? मातृभूमि अपने बच्चों को, अपनी संतान को भोजन देती हैं, अन्न, जल और वायु देती हैं, रहने का स्थान देती हैं, क्या उसको इस देश में मां के रूप में न माना जाए? क्या मातृभूमि न कहा जाए? क्या इस भारत माता को पवित्र न माना जाए? क्या इसकी इज्जत न की जाए?इसको किताब में से क्यो हटा दिया जाए? क्या देश भक्ति नहीं रहेगी? हमने पाठ्यक्रम के अंदर इसकी कोशिश की कि बच्चों के अंदर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का स्वाभाविक गुण निर्मित हो और अब यहां कहा जा रहा हैं कि इसे हटा दो। देश को माता मत मानो। देश के प्रति, भूमि के प्रति आदर का भाव मत रखो। इसे हटा दो। सारी दुनिया के अंदर यह कहा जाता हैं कि आज से नहीं हमेशा से हजारों साल से भारत में ही नहीं सारी दुनिया में अर्थ को मातृभूमि के तौर पर, मां के तौर पर माना जाता हैं लेकिन आप कहते हैं कि उसे हटा दों। क्यो? क्योंकि उसमें से देशभक्ति की भावना नजर आती हैं। मार्क्सवादी विचार में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति- ये सब प्रचलित नहीं हैं। वे इसको स्वीकार नहीं करते इसलिए यह सरकार भी स्वीकार नहीं करेंगी। यह कौन-सा तर्क हैं? फिर वैदिक civilization को बताते हुए पुस्तक में लिखा हुआ हैं the rivers like the Ganga, the Yamuna, the Saraswati, the Indus and the Satlej are mentioned in the Rig Veda. The Saraswati was considered as the most sacred river. हैं, इसको हटा दो। अब गंगा पवित्र मानी जाती हैं तो इसको हटा दो? लाखों करोड़ो लोग गंगा में स्नान करते हैं। मैं तो इलाहाबाद का रहने वाला हूं। सात-सात करोड़ आदमी गंगा में कुम्भ स्नान करने के लिए आते हैं। किसलिए आते हैं?खुवाहमखाह आते हैं? क्या टूरिज्म के लिए आते हैं? क्या मजा लेने के लिए आते हैं? भक्तिभाव से आते हैं, गंगा को पवित्र मानते हैं इसलिए आते हैं। आप कहते हैं कि इसको हटा

दो। The Saraswati was considered उस बेचारे ने यह भी नही कहा कि सरस्वती को आज भी आप पवित्र मानो। वैदिक काल में सरस्वती को पवित्र माना जाता था। नहीं, देश के लिए, देश की नदियां के लिए, देश के पर्वतों के लिए, देश के महत्वपूर्ण स्थानों के लिए किसी के मन में आदर पैदा न हो सके, किसी के मन में श्रद्धा पैदा न हो सके, ऐसी बातें आज इस नयी सरकार के द्वारा कराए जाने की कोशिश हो रही हैं। मैं इससे बहुत ज्यादा समय इन बातों को पढ़ने में नहीं लूंगा। केवल एक ही बात कहूंगा। इसी वैदिक सभ्यता के संदर्भ में कहा गयाThe child marriage was unknown. One could marry the person of her own choice. The wife and husband were part of all social and religious ceremonies. Women were respected and some enjoyed even the status of *Rishis.* Father's property was inherited by all his children. इसमें यह कहा गया हैं कि आप यह हटा दीजिए किWomen were respected and some enjoyed even the Status Of *Rishis.* क्यों हटा दें? क्या यह सिखाना चाहते हैं कि देश में कमी महिलाओ की इज्जत रही ही नहीं?क्या बताया जाएगा कि वेदों में महिलाओं ऋषि के समतुल्य नहीं मानी गयी? क्या बताया जाएगा?जो टेक्स्ट बुक में लिखा हैं, जो वहां मौजूद हैं, जो सत्य है, जिसे सारी दुनिया जानती हैं, आपक कहते हैं उसे हटा दो। क्यों हटा दो? यह एक दृष्टिकोण हैं कि प्राचीन भारत में जो कुछ अच्छा था, उसे नष्ट कर दो। इससे तो यह सकेंत जाता हैं कि बच्चों का बाल विवाह नहीं होना चाहिए, भारत की परम्परा नहीं हैं।Child marriage was unknown. इससे यह पता चलता हैं कि वहां विवाह के मामले में स्त्री और पुरूष को विवाह करने के लिए स्वतंत्रता थी और जिसे आज की बडी माडर्न और बड़ी आधुनिक चीजें कहा जाता हैं, वे विघमान थीं। अगर आप यह पढ़ाएगें, इस तरह से करेंगे और इस तरह की चीजों को किताबों से हटाने के लिए आप एक कमेटी बनाएंगे और कहेंगे कि किताबों में बड़ा सैफ्रनाइजेशन हैं। एक भी उदाहरण इस रिपोर्ट के अंदर, मैंने देखा हैं, सैफ्रनाइजेशन का, कम्युनलाइजेशन का या किसी धर्म का किसी सस्कृति पर आरोप का नहीं हैं।

हां, अगर मार्क्सिज्म को आप यह मान लेते हैं कि वहीं ठीक हैं और उसी के हिसाब से, उसी दृष्टिकोण से सारा इतिहास चलेगा, तब तो मुझे कुछ नहीं कहना हैं क्योकि मुझे लगता हैं कि इस सरकार के ऊपर कम्युनिष्ट पार्टी का काफी दबाव हैं। मेरे पास 6 जुलाई का, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को दिया गया एक आदेश हैं, जिसमें सरकार ने यह कहा हैं कि "वेदान्त" "तिरूकुलर" और "आलोक केंद्र हैं शिक्षक"- इन तीनों पुस्तको की छपाई रोक दी जाए। अब यह हैं "तिरूकुरल"। चिदम्बरम जी अभी चले गए हैं, उन्होने तो अपने बजट भाषण के अंदर इसका उल्लेख किया था, इससे उद्धरण दिया था और तिरूकुरल" का तो पूरे देश में बहुत सम्मान हैं और इन्होने कहा है कि इसको मत छापो। फिर हैं "वेदान्त" यह डा. कर्ण सिंह की लिखी हुई पुस्तक हैं, एन.सी.ई.आर.टी. ने छापी हैं। इसके लिए भी कहा गया इसको मत छापो। तीसरी पुस्तक थी जिसका मैने नाम लिया। "आलोक केंद्र हैं शिक्षक", कि जिन शिक्षकों ने स्वाधीनता संग्राम में और देश के निर्माण में काम किया है, उनकी जीवनी शिक्षकों के सामने जाए ताकि शिक्षकों को यह पता लगे कि आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए। कह दिया, मत छापो। क्यों? उसमें हिंदुत्व होगा। अब अगर "वेदान्त" छप गईद्व "वेदान्त" डा. कर्ण सिंह लिख सकते है- इसमें हिंदुत्व नहीं हैं, "तिरूकुरल" जो धर्म,अर्थ, काम, मोक्ष की पुस्तक हैं – जो चार वेद हैं- उसी के बारे में, व्यावहारिक जीवन के बारे में लिखा गया है, उसमें हिन्दुत्व नहीं हैं, लेकिन जो "आलोक केंद्र हैं शिक्षक", उसमें हिंदुत्व आ गया, सैफ्रनाइजेंशन आ गया, उसमें टॉक्सिक

आ गया। वह टॉक्सिक ऐसा आया कि जो मार्क्सवादी पार्टी को तो मंजूर था ही नहीं, लेकिन अब आपको भी मंजूर नहीं हो रहा हैं। फिर एक और पुस्तक हैं, "ग्लोबल ऐजुकेशनल चेंज", इसके बारे में डी.राजा साहब ने चिट्ठी लिखी 6 जुलाई को।

"Dear Shri Arjun Singhji, we understand that NCERT Publications Department is going to print and publish a book under the title, Global Educational Change, a compendium of international documents. We also learn that Mr. J.S. Rajput will be the Editor-in-Chief of this. We are of the view that this is not proper for the NCERT to do it, particularly at a time when you have taken up the task of detoxification in the field of education."

इसमें क्या टॉक्सिक हैं? सारी दुनिया के अंदर इस ग्लोबलाइजेशन के समय जो रिपोर्ट्स हैं, वे इसमें सक्षेप में दी गई हैं ताकि हर अध्यापक को यह पता लगे कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में क्या चेंजेज हो रहे हैं और इसके ऐडिटर्स हैं –आर.के.सिंघल. सेक्शन ऐडिटर कहीं टी.एन.धर. हैं कहीं हैं जे.एल.आजाद, कहीं हैं श्री ओ.एस.देवाल और योगेश कुमार अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोग हैं और कहा जा रहा हैं इसमें"Learning the Treasure Within" यह एक रिपोर्ट हैं, बहुत बड़ी रिपोर्ट है युनेस्को की International Conference on Education, इसमें कौन सा भगवाकरण हैं इंटरनेशल कॉन्फ्रेस में?International Conference on Education, 45th Session. Education Sector Strategy, Priorities of Strategy on Education, Literacy and Primary Education, the Dynamics of Education Policy-Making.

इस पर आप कहते हैं कि ये टॉक्सिक हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें कौन सा सैफ्रनाइजेशन हैं, कौन सा टॉक्सिन हैं? क्या चीज हो रही हैं, जो आप बराबर कहते हैं कि इसको छापना बंद कर दो। उसका छापना बंद कर दें क्यों? किसलिए? क्या अगर किसी किताब में वेदान्त हैं, भारतीय सस्कृति या हिंदुत्व से संबंधित कोई बात हैं, हिंदू धर्म-शास्त्र से संबंधित कोई बात हैं, तो वह छापना ही बंद कर दें? क्या बात है इसमें? भारत इतना बड़ा देश हैं, इतना विशाल इसका इतिहास हैं। यह कहा जा रहा हैं एक पुस्तक के बारे में कि आपने इस पुस्तक में प्राचीन भारत को बहुत स्थान दिया हैं और माध्यकालीन भारत को कम स्थान दिया हैं। आधुनिक भारत को भी कम स्थान दिया हैं और मध्यकालीन भारत को कम स्थान दिया हैं। आधुनिक भारत को कम स्थान दिया हैं। अब अगर भारत बहुत प्राचीन देश हैं, 8000 साल का इसका इतिहास हैं, तो प्राचीन भारत का तो एक बहुत विशाल भाग होगा ही होगा। उसको डिनाई करने का मतलब हैं? हां, मार्क्सवादी उसको डिनाई करने का क्या मतलब हैं?हां, मार्क्सवादी उसको डिनाई करते हैं क्योंकि मार्क्स ने लिखा था कि हिंदुस्तान का कोई इतिहास नहीं हैं। हिंदुस्तान का अगर इतिहास हैं तो वह पराजय का इतिहास हैं। अगर हिंदुस्तान का कोई इतिहास हैं तो वह नॉन रेजिस्टैंस का इतिहास हैं। मेरे पास मार्क्स का लेख हैं, मैं इसे पहले भी सदन में पढ़ चुका हूं। I "Marx Angels, The First Indian War of Independence, 1857-1859. Progress Publication", मॉस्को का छपा हुआ हैं और इसमें कार्ल मार्क्स ने जो कहा हैं, वह मैं पढ़ देता हूं:

"Indian society has no history at all, at least, no known history."

तो जब known हिस्ट्री हैं ही नहीं, तो इतनी पुरानी हिस्ट्री आ कहां से गई? इसलिए उसको कैसे लिखा जाए? अगर उसको लिख दिया जाए तो मार्क्स की इस आवधारणा पर आघात हो जाता है।

"What we call history is but the history of the successive intruders who founded their empires on the passive basis, that unresisting and unchanging society. The question, therefore, is, not whether the English had a right to conquer India, but whether we are to prefer India conquered by the Turks, by the Persian, by the Russian, to India conquered by the British." *am* आप भारत को कैसा भारत बनाना चाहते हैं। वह तो पराजित ही रहेगा। चाहे आप अंग्रेजों की तरफ से पराजित हो जाएं, चाहे रशिया से हो जाएं, चाहें तुर्को से हो जाएं और चाहें किसी और से हो जाएं, आपका कोई इतिहास नहीं हैं। आपके अंदर कोई प्रतिरोध क्षमता नहीं हैं। आप आक्रमणकारियों के सामने हमेशा लेट गए हैं। आपने कोई प्रतिरोध नहीं किया हैं। यह क्या हो रहा है? हम अपने देश के बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं। हम उनका बिल्कुल पराजित देश बनाना चाहते हैं। बिल्कुल निकम्मा और निष्क्रिय देश बनाना चाहते हैं। उसकी गौरवशाली परम्परा का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास ज्यादा हो गया तो कौन सा गुनाह हो गया। यह तो देश को गौरव होना चाहिए कि हमारे देश का इतिहास कितना पुराना हैं। इस पुरानेपन की जितनी भी तिथियां हैं, उन तिथियों पर अनेक प्रकार की जितनी भी खोज हैं हैं, वे सारी खोज उस पुरातत्व के इतिहास में आज हमारे इतिहास की प्राचीनता को और पीछे ले जा रही हैं। लेकिन इस बारे में आपत्ति हैं कि प्राचीन भारत को क्यों ज्यादा बताया गया हैं, मध्य कालीन को क्यों ज्यादा नहीं बताया गया। क्या इस देश का इतिहास केवल 700 एडी से शुरू होता हैं या केवल फर्स्ट एडी से शुरू होता हैं या इतिहाय 5000 या 6000 बीसी से शुरू होता हैं? इस बारे में विचार होना चाहिए कि भारत का इतिहास कितना पुराना हैं। आप इस चीज को अनदेखा करके सिर्फ हमे मध्य कालीन इतिहास पढ़ाना चाहते हैं। मोहम्द बिन कासिम के हमले से इतिहास को शुरू करना चाहते हैं।द क्या बात हैं, अंग्रेजों के जमाने का इतिहास पढ़ाना चाहते, इस जगत गुरू भारत का इतिहास नहीं पढ़ाना चाहते।इसमें आपको saffronization की गंध आती हैं। इसमें आपको टोक्सिक नजर आता हैं और मार्क्स की इन सारी चीजों में आपको सेक्युलरिज्म और प्रोग्रेकसिविज्म नजर आता हैं। मंत्री जी आप इस देश की शिक्षा के साथ क्या करना चाहते हैं। आप क्यों मखौल कर रहे हैं, क्यों इस देश की शिक्षा को बरबाद करने पर तुले हैं? फिर यह कहा गया कि साहब हम पुरानी पुस्तको को पढ़ाएंगे, विद एडवाइजरी में। पुरानी पुस्तकों में क्या बाते थी? जरा उनको तो देखिए,जिनको फरि से पढ़ाना चाहते हैं। पहली बात तो यह हैं कि मैं आपको बता दूं कि उसमें गुरू तेग बहादुर के बारे में क्या लिखा था?

"In 1675, Guru Tegh Bahadur was arrested with five of his followers, brought to Delhi and executed. The official explanation for this as given in some later Persian sources is that after his return from Assam, the Guru, in association with one Hafiz Adam, a follower of Shaikh Ahmad Sirhindi, had resorted to plunder and rapine, laying waste the whole province of the Punjab." यह गुरू तेग बहादुर जी के बारे में कहा जा रहा हैं और यह

पढ़ाया जा रहा हैं। जब हमने पूछा कि यह कौन सा Persian source हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर ऐसा source बताया गया जिनसे गुरू तेग बहादुर के समय से और सौ साल का अंतर था। डा. महीप सिंह ने और तमाम सिख विद्वानों से इसके बारे में चर्चाएं की। लेखक से पूछा कि ये कहां से लाए हो? उसका कोई जवाब नहीं हैं। फिर जब हमने इन पुस्तको को बदला तो ऐसे ही नहीं बदला। हमारे पास शिकायते आई थी। पंजाब हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। दिल्ली असेम्बली ने प्रस्ताव पास किया था। मेरे पास दिल्ली असेम्बली का वह प्रस्ताव हैं, जिसमें उन्होंने यह कहा कि किताबों से ये हिस्से निकाल दिए जाएं। इनको बदल दिया जाए। दिल्ली विधान सभा ने इसके ऊपर प्रस्ताव पास किया हैं। वह प्रस्ताव पास करने के बाद उन्होने हमारे पास भेजा हैं। .....(समय की घंटी).... तब उसके बाद हमने इन पुस्तको को बदला हैं। इसी तरह से जैन धर्म के बारे में लिखा गया, हम तो सर्व धर्म समभाव पढ़ाना चाहते हैं। पुरानी पुस्तक में लिखा गया कि जैन धर्म की संस्थापना महवीर जी ने की थी। जैन धर्म वालो से पूछा तो उन्होने कहा कि पार्श्वनाथ ने की थी। पुस्तक कहती हैं कि तेइस तीर्थकर काल्पनिक, और इसलिए काल्पानिक थे क्योंकि जैन धर्म अपने को प्राचीनतम स्थापित करना चाहता था। आप बच्चो को यह पढ़ाना चाहते हैं। आप बच्चो में क्या मानसिकता डालना चाहते हैं? उनको आप प्रत्येक धर्म के बारे में अरूचि, वितृष्णा और उसमें गलतियां हैं, यह बताना चाहते हैं। जाटों को लुटेरा बताया गया हैं। मंत्री जी, विदेश मंत्री जी, आप लूटमार करने वालो में से हैं। यह पुस्तक में लिखा हुआ हैं और यही लिखा गया था कि सूरजमल जाट, वे भरतपुर में लूटमार करते थे और सारे देश में त्राहि-त्राहि मची हुई थी।....(व्यवधान)... मैं आप से तभी कह रहा हूं। आपने जो लिखा हैं, वह इसमें नहीं हैं और जो अपने लिखा हैं, वह इसमें नहीं हैं। जो इसमें लिखा हैं, उसका आपने पता नहीं पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अब इन पुस्तकों को फिर से पढ़ाया जाए, कहा जा रहा है, फिर से पढ़ाइए। यह सारी दुनिया को बताइए। फिर कहा गया कि प्राचीन भारतवर्ष में गोमास खाया जा रहा हैं।

हमने पूछा कि कहां से लिया, किन पुस्तको मे हैं? कहा गया कि वेदो में हैं। हमने कहा कि चारों वेद यहां रख देते हैं, बताओं कि कहा से हैं? नहीं बता सके क्योंकि ओरिजनल वेद तो पढ़े नही थे और सस्कृत जानते थे, लेकिन उन्होने लिख दिया कि प्राचीन भारत में गोमांस खाया जाता था। फिर यह लिखा हैं कि वे गोमांस तो खाते थे, मगर पोर्क नहीं खाते थे। यह क्या बात हैं? इससे आप क्या यह साबित करना चाहते हैं कि प्राचीन भारत में गोमांस खाया जाता था, मगर पोर्क नहीं खाया जाता था। इससे क्या सिग्नल्स देना चाहते हैं? ...(समय की घंटी)... उपसभाध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, देश के भविष्य से संबंधित हैं, देश के पूरे उत्थान और पतन से संबंधित यह प्रश्न हैं

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया): आप तो ब्रीफ में बहुत बड़ी बात बोल जाते हैं। आपका काफी समय हो गया हैं, इसलिए आपसे समापन का अनुरोध करता हूं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : उपसभाध्यक्ष जी, इसमें जितना समय लगेगा, उतना कम हैं। यह समय तो बहुत आवश्यक हैं। देश को इस पर बहस करनी चाहिए।

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश)**:** पूरे देश का चरित्र निर्माण कर रहे हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : पूरे देश के भविष्य का सवाल हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया): देखिए, आप बहस करना चाहते हैं, तो दिन भर बहस कीजिए, लेकिन इसके लिए फिर से अलग से समय लेना होगा, जो आपका आज का समय हैं, वह पूरा हो गया हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : उपसभाध्यक्ष जी, मैं थोड़ा और पढ़ना चाहता हूं। यह कहा गया कि इस देश में जो भक्ति मूवमेंट हैं, यह फ्यूडिज्म हैं। भक्ति मूवमेंट सामंतशाही से शुरू हुआ। क्यों? आर.एस. शर्मा एनशिंएट इंडिया की पुस्तक में कहते हैं, "It meant that the devotees completely surrendered to their God. This practice can be compared to the complete dependence of the tenants on the landowners. Just as the tenants offered and rendered various services to the Lord and then received land and protection as kind of favour from him, a similar relation came to be established between individual and his God. Since alumnus of feudalism persisted in the country for a very long time, *bhakti* came to be deeply embedded in the Indian ethos इस देश में फ्यूडलिज्म कहां था? इतिहास के किस ग्रंथ से लिया हैं? क्योंकि मार्क्स कहता हैं कि सोसायटी के विकास में फ्यूडलिज्म, कैप्टलिज्म, निश्चित रूप से सीढ़िया हैं, हर देश में यह होना ही चाहिए। अगर यह नहीं हैं तो रिवोल्यूशन ऑफ सोसायटी नहीं होगा। मार्क्सिज्म के हिसाब से न पहले कभी चला था, न आज चल रहा हैं और मैं यह बताना चाहता हूं कि न आगे कभी चलेगा। इस देश में कहते हैं कि भक्ति भाव फ्यूडलिज्म से हैं। क्या कबीर फ्यूडलिज्म सोसायटी को रीप्रेजेन्ट कर रहे थे, नानक फ्यूडलिज्म सोसायटी से पैदा हुए थे, तुलसीदास फ्यूडलिज्म सोसायटी से पैदा हुए थे? खैर तुलसीदास का जिक्र तो इनकी पुस्तको में हैं ही नहीं। क्या सूरदास भक्ति मूवमेंट में वहां से पैदा हुए थें? क्या रामानुज उसमें से पैदा हुए थे? ये फ्यूडलिज्म सोसायटी के रीप्रेजेन्टेटिव थे? इस देश के लोगों को क्या बातें बताई जा रही हैं? इस देश को इस देश की दृष्टि से देखना चाहिए। आप इस देश के यूरोप की दृष्टि से, अन्य देशों की दृष्टि से देखकर लिखेंगे, मार्क्स की दृष्टि से देखकर लिखेंगे? यह नहीं हो सकता हैं। इस देश को इस देश की दृष्टि से देखकर लिखना चाहिए। फिर कहा जाता है कि साहब, यह जो हिंदुत्व हैं, यह तो और संस्कृति हैं ....(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया): अच्छा आप यह बताइए कि क्या यह संभव हैं कि हर किताब से आप जो भी कोट कर रहे हैं, सबका डिसकशन यहीं होगा और फिर यहीं निर्णय होगा। पार्लियामेंट तो यह नहीं कर सकती हैं। आप एक सैम्पल डिसकशन कर सकते हैं। उसकें बाद मिनिस्टर से मिलकर ...(व्यवधान)...

डा. मुरली मनोहर जोशी : उपसभाध्यक्ष जी, जब तक सैम्पल के द्वारा भयानकता देश के सामने नहीं रखी जाएगी....(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया) : आपने ऑलरेडी बहुत भयानक चित्र पैदा कर दिया हैं...(व्यवधान)... और कितना भयानक करेंगे?

डा. मुरली मनोहर जोशी : उपसभाध्यक्ष जी, अभी तो मुझे बहुत कुछ बनाना हैं, यह सब रखा हुआ हैं, ये सब उस भयानकता के सबूत हैं। ये सब उस भयानकता के सबूत हैं, जो पढ़ाए जा रहे हैं किताब में ...(व्यवधान)... ये क्या पुस्तकें बनी थी, जिनमें राणा प्रताप को लुटेरा

बताया जा रहा हैं, जिसके अंदर शिवाजी को एक रैबल बताया जा रहा हैं ...(व्यवधान)... क्या बातें आप कर रहे हैं ...(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया) : इसका मतलब हैं कि आपके लिए जितना समय हैं, आप उससे डबल समय लेना चाहते हैं। अब आप एक घंटा और बोलना चाहते हैं, कुछ तो बताएंगे ...(व्यवधान)...

डा. मुरली मनोहर जोशी : कृपा करके ध्यानपूर्वक सुनें। यह बहस आज सदन में फिर से उठी हैं और यह उठानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसे स्पष्ट कर देना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया): लेकिन समय की पाबंदी तो रखनी पड़ेगी ...(व्यवधान)...

डा. मुरली मनोहर जोशी : समय की पांबदी ....(व्यवधान)...

श्री विक्रम वर्मा : थोड़ा समय दे दीजिए ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया): थोड़ा समय, मतलब आप कितना समय चाहते हैं, यह बताइए।

डा. मुरली मनोहर जोशी : उपसभाध्यक्ष जी, जब यह बहस होती हैं और जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं ....(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया): आप सब जानते हैं कि अनलिमिटिड समय नहीं दिया जा सकता हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं। अगर आप डिसीप्लीन नहीं रखेंगे तों क्या हम इस डिसकशन को अंत तक चालू रखे? आप यह बताइए कि आपका जितना समय हैं उससे ज्यादा समय आप ले चुके हैं, फिर भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप और कितना समय तक बोलना चाहते हैं ...(व्यवधान).... क्या आप बिना समय के बोलते रहेंगे ...(व्यवधान)...

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति जी, महत्वपूर्ण विषयों पर ...(व्यवधान)...

श्री विक्रम वर्मा : सभापति जी, यह महत्वपूर्ण विषय हैं ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया) : मैं उनकी सुनूं या आपकी सुनूं ...(व्यवधान)... आप लोग एक साथ बोल रहे हैं, एक-एक करके बोलिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं....(व्यवधान).. बोलिए क्या बोलना चाहते हैं?

श्री विक्रम वर्मा : हम यह कहना चाहते हैं कि इससे पहले भी इस सदन में कई विषयों पर इससे ज्यादा लम्बी बहस हुई हैं। यह महत्वपूर्ण विषय हैं और जिन पुसतकों में परिवर्तन किया जा रहा हैं, उन्हीं का उल्लेख किया जा रहा हैं, परिधि से बाहर बात नहीं जा रही हैं। इसका ध्यान आकर्षित करने के लिए ही तो प्रश्न आया हैं ...(व्यवधान).. यह तो हमारा निवेदन हैं ...(व्यवधान)...।

श्री बलबीर के. पुज (उत्तर प्रदेश): महोदय, पहले भी बहुत बार वक्ताओं ने ज्यादा समय लिया हैं और आप ने उन्हें समय दिया हैं, आज डा. जोशी थोड़ा ज्यादा समय ले रहे हैं तो इस में कृपणता मत दिखाइए।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया): यह कृपणता की बात नहीं हैं, आज यह डिस्कसन खत्म करना हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : उपसभाध्यक्ष जी, मैं बहुत कम Intervene करता हूं और सामान्य तौर पर जब विषय बहुत महत्वपूर्ण होता हैं या राष्ट्र की दूष्टि से महत्वपूर्ण होता हैं, तभी इस सदन का समय लेता हूं। मेरी दृष्टि में यह बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। यह देश के भविष्य से संबंधित विषय हैं। पिछले 57 सालों में जो इस देश के साथ हुआ हैं, जैसी पीढ़ियों का निर्माण हुआ हैं, जैसे देश की वास्ताविकता से अनभिज्ञ लोग रख दिए गए हैं, उस का परिणाम आज शिक्षा के अंदर देखने को मिलता हैं। आप देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में आज नौजवानों में क्या हालात पैदा होगए हैं। उपसभाध्यक्ष जी, जब से वैल्यू बेस्ड शिक्षा खत्म हुई हैं ...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया):मैं आप की किसी बात के ऊपर टिप्पणी नहीं करने वाला, मैं केवल समय की बात कर रहा हूं। मैं ने आप से सिर्फ यही पूछा हैं कि आप को कितना समय और चाहिए क्योंकि Unlimited time देने की मेरी पावर नहीं हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं unlimited time नहीं लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोंदिया): आप यह बता दीजिए कि आप को 5 मिनिट चाहिए, 10 मिनिट चाहिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं 10 मिनिट और लूंगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप देखिए कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सन् 1948 में अलीगढ विश्विघालय के convocation में क्या कहा था, भारत के इतिहास और भारत की संस्कृति के बारे में उन्होंने क्या कहा था। उन्होने कहा था"I am proud of India, not only because of her ancient, magnificent heritage but also because of her remarkable capacity to add to it by keeping the doors and windows of her mind and spirit open to fresh and invigorating winds from distant lands. India's strength has been two-fold; her own innate culture which flowered through the ages, and her capacity to draw from other sources and added it to her own."

"I am proud of our inneritance and our ancestors who gave an intellectual and cultural pre-eminence to India. Now do you feel about this past?" He is addressing the Aligarh University. "Do you feel that you are also sharers and inheritors of it, and therefore, proud of something that belongs to you as much as to me? Or do you feel alien to it and pass it by without understanding it or feeling ,that strange thrill, which comes from the realisation that we are the trustees and inheritors of this vast treasure? You are Muslims and I am a Hindu. We may adhere to different religious faiths or even to none; but that does not take away from that cultural inheritance that is yours as much as it is mine." TIF cultural inheritance जिस को आप

हटाना चाहते हैं, जिस के बारे में आप कह रहे हैं कि भारत की इस cultursl inheritance को क्यों पढ़ाना चाहते हैं? ...(व्यवधान)..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): आप He can protect himself. He does not need your protection.

डा. मुरली मनोहर जोशी : फरि कहा जा रहा हैं कि हिन्दुत्व की एक अंतर्धारा इन पुस्तकों में बह रही हैं।The report says...*(Interruptions)*... reading between theइस में कुछ ऐसा लगता हैं कि जैसे हिंदुत्व प्रवाहित हो रहा हैं। तो हिंदुत्व क्या हैं, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट कहती हैं

"Thus, it cannot be doubted, particularly in view of the Constitution Bench decisions of this Court that the words 'Hinduism' or 'Hindutva' are not necessarily to be understood and construed narrowly, confined only to the strict Hindu religious practices unrelated to the culture and ethos of the people of India, depicting the way of life of the Indian people. Unless the context of a speech indicates a contrary meaning or use, in the abstract these terms are indicative more of a way of life of the Indian people and are not confined merely to describe persons practising the Hindu religion as a faith." It is a way of life, यह जीवन का दृष्टिकोण हैं। यह वही हैं जिस को पंडित जी कहा कि "We are the inheritors of that great culture."उस सांस्कृतिक मूलधारा को आप कोई भी नाम दे दीजिए। कुछ कहेंगे यह भारतीयता हैं, कुछ कहेंगे indianess है, कुछ कहेंगे हिंदोस्तानियत हैं। जो आप की मर्जी हो, वह नाम दे दीजिए, लेकिन यह भारत की मूलधारा हैं जो कि शिक्षा में प्रभावित होनी चाहिए, जो इस के नौजवानों के खून में प्रवाहित होनी चाहिए। देशभक्ति, मातृभक्ति, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास की गौरव गाथा को इस देश के नौजवानों को नहीं भूलना चाहिए और वह हम शिक्षा के अंदर करना चाहते हैं। फिर कहा जाता हैं कि भगवाकरण किया। मैं कांग्रेस कमेटी की 2 अप्रैल, 1931 की करांची में संपन्न बैठक की रिपोर्ट का उद्धरण देना चाहता हूं जो कि देश के झंडे के बारे में थी भारत के झंडे का रंग कैसा हो। महोदय, उस कमेटी के सम्मानीय सदस्य थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद,मास्टर तारासिंह, पंडित जवाहर लाल नेहरू, प्रिंसिपल डी.जी. काललकर, डा. एन.एस. हार्डीकर और डा. वी. पट्टाभिसीतारमैया।

मैं पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ता, लास्ट का हिस्सा पढ़ता हूं –before the Committee was recognised to be both difficult and delicate. There was a consensus of opinion both in the committee and in the public that responded to the questionnaire that the colours of the Rag should not bear any communal significance. While it is true that the Congress never countenanced any communal interpretation of the colours of the Rag, the fact remains that when it was originally conceived the two colours chosen namely red and green, were selected on this basis and stood for the Hindu and Muslim, Communities, and later the white colour was added being meant to stand for the remaining communities of India, the Sikhs had all along objected to this assortment of colours etc.etc." डिसकशन यह हो रहा था

5.00 p.m.

कि इसके तीन रंग तीन कम्युनिटीज को डीनोट करते हैं।"It remains for the committee now to approach the question of colours and device for the National Flag wholly from an aesthetic and heraldic standpoint. We feel the flag must be distinctive, artistic, rectangular and non-communal. Opinion has been unanimous that our National Flag should be of a single colour expect for the colour of the device. If there is one colour that is more acceptable to the Indians as a whole, even as it is more distinctive than another, one that is associated with this ancient country by long tradition, it is the Kesari or saffron colour..."

This is the report signed by all these people.आज आप कहते हैं किSafforn is a dirty word, वह कहते हैं वैदिक टाइम से यह कलर इस देश में चला आ रहा हैं। उस कलर को आप कहते हैं सैफर्नाइजेशन, डिटोक्सीफिकेशन। क्या आप भारत के तिरंगे झंडे से सैफर्न कलर हटानें की हिम्मत रखते हैं? क्या बातें बताई जा रही हैं इस देश के अंदर। आखिर में मैं कनक्ल्यूड करूंगा, जो गुरू रवीन्द्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1903 में "हिस्ट्री आफ भारतवर्ष" के ऊपर भाषण किया था, उसका अंग्रेजी अनुवाद मेरे पास हैं, मूल भाषण बांगला में हैं। उन्होंने कहा था –

> "The history of India that we read and memorize for our examinations is really a nightmarish account of India. From which quarter can we derive our life-sustenance when we leam that our tie with our own country is so insignificant? In such a situation we feel no hitch whatsoever in installing others' countries in place of our own.
>
> By not viewing Bharatavarsha from Bharatavarsha's own perspective, since our very childhood, we learn to demean her and in consequence we get demeaned ourselves. An English boy knows that his ancestors won many wars, conquered many lands and did extensive trade and commerce; he too wants to be an heir to the glory of war, of wealth, of success in commerce. We leam that our ancestors did not conquer other countries and did not extend trade and commerce; to make this fact known is the very purpose of the history of India..."
>
> इतिहास जो आप पढ़ाना चाहते हैं, उसमें यही होगा। आप कभी भारत को उसका मुख्य स्थान देने नहीं देंगे। आप भारत के बारे में कभी लोगों में गौरव, गरिमा नहीं आने देंगे और भारत के लोगों के मन में देश के लिए अभिमान पैदा नहीं होने देंगे। भारतीय संस्कृति, भारतीय उघम, पराक्रम और भारत देश ने जो कुछ दुनिया को दिया हैं, उसके बारे में आप सारी स्थिति से लोगों को अज्ञान में रखना चाहेंगे।

इससे बड़ा और कोई अपराध इस देश में शिक्षा के साथ हो नहीं सकता।"What our ancestors did, we do not know; therefore, we also do not know what we ought to aim for. Therefore, we have to imitate others. Whom should we blame for this? The way we get our education since our very childhood, the way you are trying to educate the children of India, Mr. Minister, with every passing day we get increasingly alienated from our own country till a sense of rebellion against the land of our birth overtakes our mind."

यह हैं गुरू रवीन्द्र नाथ टैगोर। फिर कहते हैं -"And the endeavour to form communion with others, and the effort to harmonize divergences and contradictions within one's own fold are the basis of ethical and social advancement. The kind of unity that the European civilization has opted for is discord-centred; the kind of unity that Bharatavarshiya civilization has opted for is concord-centred.."

आपकी जो पुस्तकें मध्य प्रदेश के पाठ्य पुस्तक निगम ने छपवाई थीं, उसमें तमाशा यह हैं। ...(व्यवधान).. यह कक्षा 6 की पुस्तक हैं सामजिक अध्ययन की, जिसमें एशिया हैं और बाकी एशिया कें अंदर भारतवर्ष क्या हैं, यह हम नहीं समझ पाए। सिर्फ कुछ नक्शें कहीं हैं। बाकी भारत का जिक्र इसमें हैं ही नहीं। शायद एशिया का हिस्सा भारत नहीं हैं। फिर कक्षा-7 की किताब थी –यूरोप एवं अफ्रीका। इसके अंदर भी भारत का कहीं जिक्र होने का सवाल नहीं हैं। लेकिन कक्षा-8 की पुस्तक हैं- अमेरिका एवं भारत। क्या भारत का अंग हैं? क्या बच्चे को पहले एशिया पढ़ाया जाए, यूरोप पढ़ाया जाए, अमेरिका पढ़ाया जाए। भूगोल पढ़ाने का तरीका तो यह हैं कि पहले आप उसे अपना परिवेश पढ़ाएं, अपनी तहसील पढ़ाएं, अपना जिला पढ़ाएं, अपना प्रदेश पढ़ाएं अपना देश पढ़ाएं, एशिया पढ़ाए, फिर विश्व पढ़ाएं तथा ब्रहमांड पढ़ाएं तो समझ में आता हैं। लेंकिन आप शुरू कर रहे हैं कहां से –कक्षा-6 में एशिया। कक्षा-7 में यूरोप और अफ्रीका। शायद तहसील और जिला तो एम.ए. तक जाकर पढ़ाएंगे। क्या हैं यह पढ़ाई? क्या देश इस तरह से चलेगा, क्या देश में इस तरह का भूगोल बताया जाएगा, क्या देश में उस तरह का इतिहास बताया जाएगा। मैं और पुस्तकों के बारे में आज जिक्र नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इतिहास की पुस्तकों के बारे में और सामजिक अध्ययन की पुस्तकों के बारे में आदेश निकाले गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं सावधान करना चाहता हूं सरकार को, मैं सावधान करना चाहता हूं इस सदन को और देश को कि देश की शिक्षा के साथ और इतिहास के साथ कोई खिलवाड़ मत कीजिए। कोई देश, कोई राष्ट्र जो अपने इतिहास को भूलता हैं, उससे कट जाता हैं, जो अपने महापुरूषो की, अपने देश की उपलब्धियो की और अपनी कमजोरियों की ठीक मीमांसा नहीं कर सकता, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आप केवल देश को नगण्य निकम्मा, पराजित और एक बहुत छोटे से इतिहास का दौर, उसके सामने रखेंगे तो देश कभी महान नहीं बनेगा। महान देश के लिए इतिहास की महानताओं को पढ़ाने की जरूरत होती हैं, वही पढ़ाई जाएं। मैं स्वागत करूंगा अगर इन पुस्तको मे से कोई साम्प्रदायिकता, कोई संविधान के विरोध में, कोई 1986 की पलिसी के विरोध में कोई बात अगर साबित हो, तो उसे ठीक

करेंगे और हम उसकी गलती स्वीकार करेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पाठ्यक्रमों को सुधारने की प्रक्रिया क्या हैं? आप कहते हैं कि हम प्रक्रिया के मुताबिक सुधार रहे है। प्रक्रिया यह कहती थी कि हर पांच साल में इस पर विचार होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ 1986 से 1997 तक? पहले क्यों नहीं हुए इसमें रिव्यू? ये गलत बातें पुस्तकों में क्यों आ रही थी, क्यों नहीं रिव्यू किए गए? यह थी आपकी शिक्षा नीति, यह था आपके इम्प्लीमेंटेशन का तरीका। जब हमारी सरकार आई, हमने 1986 की नीतियों के अनुसार इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया जो पार्लियामेंट ने नीति पास की थी -1992 के प्लान ऑफ एक्शन के मुताबिक शिक्षा नीति के सुधार तथा शिक्षा के इम्प्लीमेंटेशन को ठीक करने की कोशिश की थी। हर पांच साल में पाठ्यक्रमों का रिव्यू होना चाहिए। हमें पुस्तकें बनाने में 3 वर्ष लगे और एक साथ हमने कभी नहीं किया, कभी समरी भी नहीं की, पूरी प्रक्रिया उसके लिए की। आपने आदेश निकाल दिया कि एक साल के अंदर सब पुस्तके बदल डालो, नई पुस्तके ले आओ। विपिन चन्द्रा को ले आओ, सतीश चन्द्रा को ले आओ,वरूण देव को ले आओ और जितने भी आपके ये पश्चिम बंगाल के मार्किसस्ट लेखक हैं, उन सब को ले आओ। जों आ कर के यह पढ़ाएगे कि इस देश का इतिहास कुछ हैं ही नहीं। ....(व्यवधान).. हौव्वा नहीं हैं मैं खतरा बतला रहा हूं। मंत्री जी, ये विषकन्याएं हैं। आप इनसे सावधान रहिए। मार्किस्ट पार्टी, कम्सुनिस्ट पार्टी – ये सब विषकन्याएं हैं। ये एक आर्लिगन जिसका करती हैं उसकी जान निकाल कर रख देती हैं, यह ध्यान में रखिए, इनसे सावधान रहिए और इनके साथ आप हमेशा सावधानी रखिए। मैं बताना चाहता हूं कि आप इनसे बचकर रहिए और शिक्षा के साथ काम कीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Anything 'unparliamentary' will not go on record.

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह तो पिछली बार भी सदन में आ चुका हैं। तो श्रीमान मै आपसे अनुरोध करूंगा कि ठहरिए, सोचिए, अपनी आंतरिक राजनीति को ठीक करने के लिए आप शिक्षा के साथ कोई खिलवाड़ मत कीजिए। आप अपने आप चाहे जो ....(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया) **:** अब आपका 10 मिनिट से ज्यादा समय हो गया हैं।

डा- मुरली मनोहर जोशी : पर भगवान के वास्ते, देश का भविष्य के वास्ते, शिक्षा से खिलवाड़ मत कीजिए, भारत की महानता को खंडित मत कीजिए। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Shri Jairam Ramesh. Will you just take ten to twelve minutes?

SHRI JAIRAM RAMESH (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, you have asked me to take no more than ten to fifteen minutes, and unlike the previous speaker, this will be a short-duration intervention. It won't be a short-duration-long-punishment speech and an exercise in Indian history!

Sir, before I start, let me respond to two or three points that the distinguished former Minister for HRD made, which need to be encountered. This is both a debate which has a longer term perspective, a

larger perspective on clashing visions of Indian history, on clashing visions of Indian nationalism and a debate in the short-term exercise of the re-writing of textbooks, the redoing of curricula and syllabi by successive Governments in the last five years.

I will not get into a controversy, since 80 per cent of Dr. Joshi's intervention was directed at the Marxists and they are capable of taking care of themselves and since there is, in my view, a difference between our perspective and our Marxist friends' perspective, though they are part of our alliance. I will expand on that a little bit later.

Let me take two or three points that he has mentioned. He makes an astounding claim that, whatever was done by him in the last six years, he followed the National Education Policy of 1986. This is completely in contravention of truth. The National Education Policy of 1986, which was drafted after eight months of consultations across the country and in which the then Prime Minister himself participated, laid down a specific institutional format for the three essential pillars of education, namely, curriculum, syllabus and textbooks. I would like the present Human Resource Development Minister to explain to the House whether it is fact that in the last six years all the institutional processes embedded in the National Education Policy, namely, consultations with the Central Advisory-Board on Education, consultations with the General Body of the NCERT and consultations with the Executive Committee of the NCERT, were followed or not. He should explain to this House whether all these institutional processes identified in the National Education Policy for curriculum, from which the syllabus and the textbooks are derived, were followed or not. It is my understanding that in the last six years this institutional process of consultation and consensus building was reduced to a mockery, to an oral form of communication and interaction between a few individuals in the Ministry of Human Resource Development and the National Council for Educational Research and Training. So, the former Minister's claim that whatever he did has the sanction of the National Education Policy, which is an astounding claim, has belied the facts which I hope the present Minister will bring to bear to the House. Sir, the vision of the National Education Policy ...(I*nterruptions)...*

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I will give you the full details on how it was done. *...(Interruptions)...*

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I am not yielding. (Interruptions)... I am not yielding. *...(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया)**:** प्लीज आप इनको बोलने दीजिए। **...**(व्यवधान)**...** प्लीज बोलने दीजिए। **...**(व्यवधान)**..** वह यील्ड नहीं कर रहे हैं। **...**(व्यवधान)**...**

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I am not yielding. *...(Interruptions)...* I am not yielding. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): He is not yielding. ... *(Interruptions)...*

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I am not yielding. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): You continue. You don't listen to him. *...(Interruptions)...*

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal) : Unfortunately, you don't have the privilege of answering to his questions because you are sitting there. *...(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया)**:** प्लीज आप भी बैठ जाइये। **...**(व्यवधान)**...** आप भी बैठ जाइये। **...**(व्यवधान)**...** प्लीज बैठ जाइये। **...**(व्यवधान)**...**

SHRI NILOTPAL BASU: The people made you to sit there. ... *(Interruptions)...*

SHRI BALBIR K. PUNJ: Sir, what is this? *...(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया)**:** प्लीज बैठ जाइये। **...**(व्यवधान)**...** आप बोलिए। **...**(व्यवधान)**...**

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, let me finish my ten minutes. *...(Interruptions)...*

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I have to again quote the rules and tell him what he is supposed to do and what he is not supposed to do. He is not the Minister and he has taken 40 minutes of the House. It is only the prerogative of the Minister to reply to whatever questions Mr. Jairam Ramesh raised. *...(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया) **:** प्लीज बैठ जाइये। **....**(व्यवधान)**..** आप भी बैठ जाइये। **...**(व्यवधान)**...** बोलिए। **...**(व्यवधान)**...**

SHRI BALBIR K. PUNJ: We want to hear him. *...(Interruptions)...*

श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे (महाराष्ट्र): आपने उनको ऑथरिटी नहीं दी हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीं संतोष बागडोदिया): आप बीच में नहीं बोल सकते। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)....

SHRI BALAVANT *alias* BAL APTE: You have not permitted him. *...(Interruptions)...*

SHRI NILOTPAL BASU: Neither was Dr. Joshi permitted to get up and make his observations. *...(Interruptions)...*

श्री रवि शंकर प्रसाद : क्या देश की जनता ने इनको वोट दिया हैं? ...(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया): आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)...you please sit down. .....(interruptions) ....देखिए, आपके स्पीकर ने ज्यादा समय लिया हैं। हमने आपके अनुरोध को स्वीकारा किया। अब अगर आप दूसरे को नहीं बोलने देगे तो अनुचित बात होगी। ....(व्यवधान)... आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान).. आप अब बैठ जाइये। आप उनको बोलने दीजिए। ....(व्यवधान)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA):Please Sit down. .. .*(Interruptions)*.. आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)....

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया): आपको भी अथॉरिटी नहीं दी, उनकी भी नहीं दी। मैंने इनको भी कहा बैठ जाओं, आप भी बैठ जाओ। और मैं क्या कर सकता हूं?....(व्यवधान)...

श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे : बीच में जो बोलते हैं, वह बहुत गलत हैं, इनडीसेंट हैं....(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ादिया): अब आप बैठ जाइए।

SHRI JAIRAM RAMESH: I would make a humble request. This is a forum for debate. We nave divergent viewpoints, different perspectives. I have listened to you with rapt attention. Please accord to me the same courtesy, even though you may disagree with what I say.

My first point is that the claim that the changes that have been sought to be introduced between 1998 and early 2004 by the erstwhile Government was a direct consequence of the National Education Policy is simply not true. Institutional processes, whether it is the Central Advisory Board on Education, whether it is the General Body of the NCERT, whether it is the Executive Committee of the NCERT which, ultimately, provides the Seal of Approval for the changes in curriculum from which syllabi and textbooks are subsequently derived, have not been followed, and the entire

process of change was a highly personalised form of interaction between a few people in the Ministry of Human Resources Development and a few people in the National Council of Educational Research and Training. Now only the present Minister can actually bear this out in terms of facts, and I would request him to do so when he gives his reply to this debate.

Sir, the second claim that has been made by the former Minister of Human Resources Development is this. He referred to the Report of the Panel of Historians which was set up in June, 2004 and which submitted its Report in July, 2004. Sir, this Panel had three eminent historians, namely, Prof. S. Settar, Prof. J.S. Grewal and Prof. Barun De. Sir, Dr. Joshi himself is an eminent physicist and he knows that in all sciences, whether in social science or in physical science, peer review is the only acknowledged form of acceptance. It is not what I say or what my colleagues on the other side say. It is what the peers of economists, socialists, historians, physicists and chemists say, and that is how acknowledgement and appreciation is given. That is how the Nobel Prizes are awarded. It is based on peer review. It is the generally accepted view amongst the historian community that these three gentlemen, Prof. Settar, Prof. Grewal and Prof. Barun De, are amongst the most noted, eminent and distinguished historians of India. They may have particular political persuasions, which are not relevant here. They are the members of the Indian History Congress; in fact, every historian aspires to be a member of the Indian History Congress. And these three distinguished historians who have held the distinguished posts in academia have given a report to the Government. Now, the former Minister of Human Resource Development claims that there is absolutely no basis that this Committee did not point to any evidence of errors, of "creeping communalisation" or "creeping saffronisation". I am only using his words in this Report. I am afraid even this is not borne out by facts. This is a public document. This is available - the Report of the Panel of Historians submitted to the Ministry of Human' Resource Development on 5th July, 2004. And, I don't want to take your time by quoting extensively from this document. But let me just say that there is a wealth of evidence in this document to show the type of errors that have crept into the history books, the type of selective reading of Indian history that has gone into these history books, and the type of danger inherent in these books. Let me just quote the last five lines of this document. It says: "After a detailed analysis of various textbooks which were referred to by the distinguished member himself, the three-man Committee concludes and I quote: "On the whole,

we can see that the scope of the books under consideration is far narrower than what is expected of a good textbook of history.

'Evidence adduced by the authors is not only secondary but also partial. Their sympathies and antipathies easily come to the surface, being reflected in their tone as well as vocabulary they use. Combined with their silences, these features tend to glorify one set of phenomena and to denigrate another set of phenomena. In the process, much of the meaningful history of the people and the country is left out".

Sir, these three historians and I, and as, I am sure, many of us, are equally proud of India's past, as Dr. Joshi is. We are all knowledgeable about where we were, how we came to where we are today, the glory of Indian civilisation, its triumphs, its shortfalls. This is not the purpose of this debate. The purpose of this debate was, I thought, to look into the process of re-writing the textbooks, which has been started by the present Government, which the Opposition feels, constitutes a danger to the country. Sir, this eminent expert panel has, unlike what the previous speaker has claimed, gone into considerable detail into the history books that have been prescribed. They have pointed out, not just factual errors, but they have also pointed out, in my view and in their view, certain ideological phenomena, or, some ideological bent of mind which is inherent in the way the evidence is actually put forward in these textbooks.

Sir, the recommendation of this three-men panel, and I would like Dr. Joshi to listen to this because he made much of the fact that this Government is captive to the Marxist ideology. Sir, the recommendation of this panel was that these textbooks be withdrawn immediately and the Government of India, to which these hated, denigrated, Marxists are providing outside support, decided not to withdraw these books immediately because that would inconvenience children; these would be withdrawn only from the next academic year. This decision has not gone down very well with our Marxist friends.

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, since he has...

No, no. Let me finish. In fact, Sir, there is a wide body of opinion that feels that these books must be withdrawn immediately. But they have not been withdrawn immediately. So, to say, like the former Minister was saying, that this whole exercise is an exercise of a Government that has been captured by historians or politicians of only Marxist ideology is completely wrong. I think, this is not a debate of Marxist ideology versus

Hindu ideology. That is not the debate. The debate is simply this: Do we respect professionalism or not; do we respect academic merit or not? If we have historians who have - they may have their ideological persuasions - universally published in peer-reviewed journals; if we have historians who are universally acknowledged as experts in their fields, their views and their opinions and their writings should constitute a much greater and a much more important source of information for succeeding generations than of a narrow set of historians, whose only claim to fame is profession of a particular ideology. Sir, I hold no brief for any ideology in this battle. My concern as a liberal Indian, my concern as a parent of two children, going through the process of learning history, is that our children must be exposed to the history books written by the best historians, Indian can produce. And the fact of the matter is, in the last six years, before this Government came into power, that the professionalism and the academic excellence were at a discount. Anybody who was professionally qualified, anybody who was academically competent was automatically labelled 'Leftists'. That is not the debate. The debate is how textbooks should be written. And, textbooks, in my view, and. I am sure, all of you will agree, must be written by best historians, marshalling the best evidence that is possible within the limits of time and within the limits of knowledge.

Sir, there is a lot of ambiguity in our history; there is a lot of doubt in our history, and we cannot say many things with certainty. As we evolve, new evidence comes into force and it is the job of every reputed historian to take into account the new evidence. Any historian who does not take account of new evidence is not being true to his or her profession. So, Sir, my second plea to you is, let us not make this into a debate of Hindutva versus Marxist ideology. This should be a debate of how we restore to our academic and intellectual institutions standards of autonomy, standards of excellence, standards of intellectual integrity that, unfortunately, have been systematically destroyed over the past few years. So, this is my second plea. Sir, I know you are looking at me. Please give me five minutes more, and I will finish.

Sir, the second point which came up repeatedly during the presentation of the former Minister is, he made much of the fact for these three historians who were appointed by the Ministry of Human Resource Development to review the textbooks belonged to the Indian History Congress. Sir, it is no crime to belong to the Indian History Congress. The Indian History Congress is as much reputed professional body of historians

as the Indian Science Congress is, which Dr. Joshi has attended, and which I have attended for many years. So, every professional discipline has a professional body, and the Indian History Congress has, in my view, over the years, acquired the reputation of being the authoritative voice of the profession of historians. Now to say that the three historians who have produced this Report belong to the Indian History Congress and, therefore, their Report must be rejected, Sir, again, is a half truth. The Report of the Indian History Congress, let me remind Dr. Murli Manohar Joshi, was written by three people quite different than these three people. Please don't make it out to be that the same three people who wrote the Report of the Indian History Congress are the same people now advising the Ministry of Human Resource Development. The three historians, who have written, of the Indian History Congress and this is a Report, again it is in the public domain, which all of you may have seen, History in the NCERT Textbooks, A Report and Index of Errors, is by Irfan Habib, Subiraj Jaiswal and Aditya Mukherjee, also three very distinguished historians in their own right. Now, it is true that this panel which forms the basis of the review of textbooks by the current Ministry of Human Resource Development derives substantially from the Report of the Indian History Congress. There is no denying that fact. But, to say that this is an exact replica of the Report of the Indian History Congress, Sir, in my view, is a complete travesty of truth and is a denial of facts. It is not a minor point; it is not an irrelevant point; it is a very substantial point because in the last five to six years, a concerted effort has been made to denigrate the Indian History Congcess. To say that the Indian History Congress is a den or an *Adda* of Marxist and Leftist historians and by definition these are people whose intellectual integrity and commitment to India's glory is questionable, I reject that contention, Sir. I reject that contention precisely because of the reason that I mentioned to you earlier that this is not a debate of political ideology. Of course, there is a larger debate of political ideology, which we take to the people, and occasionally, we win and occasionally somebody else wins. That is a larger issue. There is a larger issue of clash of secular nationalism versus cultural nationalism. That is not the debate here. The debate here is limited to the process of rewriting textbooks. In my view, let me end by reiterating, Sir, the three points that we must follow an institutional process of review and consultation. That has not been followed for six years, and that is being followed now. We must have the best academic and intellectual resources mobilised to write history books, in the most objective manner on the basis of the knowledge currently available so that our children can have access to the best that our

profession can provide. That was not done in the last six years. That is being sought to be done now. Sir, I think we should not obfuscate these issues and enlarge it and take it into a philosophical domain as has been sought out to be. It is a very concrete, very specific issue of the process by which curriculum, syllabus and textbooks review takes place. I believe that this Government is well within its rights to order this review because institutional processes were subverted in the past, because basic values were subverted in the past and because academic excellence was given a go-bye. So, rather than using incendiary language like saffronisation and detoxification, I would prefer to use *...(Interruptions)...* I am not using the word saffronisation and detoxification. I am just saying, let us restore excellence to the writing of history, let us restore some basic values to the writing of history, let us make the writing of history, subject to institutional processes of consensus and consultations and not subject to the whims and fancies of a political leader or political leaders and their intellectual patrons in subordinate offices of the Ministry of Human Resource Development. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया)**:** सरला माहेश्वरी जी, आपके पास आठ मिनट हैं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल)**:**उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपसे पहले ही निवेदन करूंगी कि कृपया थोड़ा सा ज्यादा समय दे दें। उपसभाध्यक्ष जी, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो विगत छह वर्षो से काले शासन में हमें चिंतित करता रहा हैं ....(व्यवधान)... हम सबको उद्विग्न करता रहा हैं ...(व्यवधान)... उपसभाध्यक्ष जी, इस बहस की शुरूआत उन्होने की ...(व्यवधान)... अब आप कृपया करके सुनेंगे ...(व्यवधान).. जब जोंशी जी बोल रहे थे, तब मैंने एक शब्द भी नहीं कहा था, इसलिए कृपा करके शांति से सुन लीजिए। उपसभाध्यक्ष जी, इस बहस की शुरूआत भी उन्हीं के द्वारा की गई, जिन्होंने भारत के समूचे शिक्षा जगत को सांप्रदायिकता, विवेकहीनता, बुद्धि विरोध और रूढिवाद के कोलतार से पोतकर एक विकसित और समय सभ्य समाज की ओर हमारी यात्रा के पथ को उलट देने की कोशिश की। उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह बात आज ज्यादा जोर देकर कहना चाहूंगी कि जब हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री, जो विज्ञान के प्राध्यपक रहे हैं और विज्ञान का पहला सिंद्धात हैं कि विज्ञान के द्वार में प्रवेश करने से पहले सभी पूर्वाग्रहों को, सभी अघंविश्वासों को तिलांजलि देनी होगी, लेकिन मुझे अफसोस हैं कि हमारे विज्ञान का प्राध्यापक सबसे आगे बढ़े हुए दर्शन, मार्क्सवाद और उस मार्क्सवाद पर चलने वाली पार्टी को विष कन्या कहता हैं। उपसभाध्यक्ष जी, मुझे उन पर दया आती हैं और इसलिए जोशी जी के लिए मैं यह ही कहना चाहूंगी कि, खुदा हमें ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, गुलामी को बरकत समझने लगें, असीरों को ऐसी रिहाई न दे। यह रिहाई उन्ही को मुबारक हो। उपसभाध्यक्ष जी, माननीय जोशी जी वे शख्स हैं,जिन्होने अपने कार्यकाल में ह्यूमन रिसोर्स डेवलेपमेंट मिनिस्ट्री को हिंदू राष्ट्र विकास मंत्रालय में तब्दील कर दिया था और इस तब्दीली के चलते संघ परिवार से अगाध वाहवाही लूटी थी ....(व्यवधान)... आप चुप रहिए प्लीज

....(व्यवधान)... उपसभाध्यक्ष जी, जहां तक संघ परिवार का सवाल हैं, यह सर्वविदित हैं कि हिंदुत्व के विचारों की उनकी प्रेरणा के स्रोत हिटलर और मुसोलिनी रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री बलबीर के. पुंज : यह गलत बात हैं। ...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): सर, यह गलत हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) : Are you yielding? फिर आप बैठ क्यों गयी हैं? ....(व्यवधान)....If you are not yielding, then keep standing.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : आप इन्हे चुप कराइए, तो मैं आगे बढ़ूं? ..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया): आप लोग तय करिए कि आप में से कौन बोलना चाहता हैं क्योंकि इतने लोगों को एक साथ सुनने की मेरी ताकत नहीं हैं।

SHRI BALBIR K. PUNJ: Mr. Vice-Chairman, Sir, what Sarlaji is saying is falsification of history. Everybody knows that it was the Communist Party which allied with Hitler in 1939...*(Interruptions)...*

SHRI NILOTPAL BASU: We have heard all these words when Joshiji was speaking. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) : Let me reply to that.

SHRI BALBIR K. PUNJ: It was part of the Congress International. It had tied hands with Hitler...*(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया): मि. पुंज आप बोल चुके, एक मिनिट बैठिए everybody knows history, मुझे नहीं मालूम हैं। I am also part of it. आपने जो बोलना था, बोल दिया। देखिए सब के अपने-अपने विचार होते हैं। आपने जो कुछ कहा, इन लोगों ने सुना। अब आप शांति से उन्हे अपनी बात कहने दीजिए। अगर आप हर सेंटेंस मे बोलने लगेगे कि इस का मतलब यह हुआ, तो फिर यह चर्चा नहीं हो सकती हैं। सरला जी, बोलिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगी कि पहले आप लोग गोलवलकर को पढ़ लें,फिर आकर बोलें।....(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया): अगर वह गलत बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए और जब आप का नंबर आए तो उसे correct कर दीजिए। please don't intrerrupt.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभाध्यक्ष महोदय, फासीवादियों का सवाल हैं, वे शिक्षा को अपना एक प्रमुख अस्त्र समझते थे। हिटलर ने अपने मंत्री को लिखा था, शिक्षा लगातार निगरानी करनी चाहिए और प्रसारित सामग्री का पालन। ज्ञान, जीवन की एक सहूलियत हैं, उस का मकसद नहीं। सन् 1929 में मुसोलिनी ने संसद को बताया कि शिक्षा के मालिक हम हैं। हमारे धर्म के अनुसार शिक्षा चलेगी। उपसभाध्यक्ष जी, हमारे देश में भी, जोशी जी चले गए हैं,

जोशी जी के काल में शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल यही हुआ है। जोशी जी ने अपने 6 वर्षो के कार्यकाल में हमारी शिक्षा और संसकृति को पूरी तरह अपने हाथ में लेकर उस की दशा और दिशा दोनों बदल दिए थे। महोदय, यह ख्यति जोशी जी को हो जाती हैं कि एन.डी.ए. के 6 वर्षो के शासन काल में इन का मंत्रालय ही सब से अधिक चर्चा का विषय रहा। महोदय, यह जोशी जी ही थे, जिन्होने खुले आम यह घोषण की कि वे भारतीयकरण, राष्ट्रीयकरण और आध्यात्मीकरण के जरिए हमारी शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प कर देंगे। ....(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): आप उन्हें बोलने दीजिए। आप हर बार इंटरप्ट करेंगे? आप एक महिला को इंटरप्ट कर रहे हैं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी :उपसभाध्यक्ष जी, ये महिला को इंटरप्ट नही कर रहे हैं। ये सच्चाई को छुपाना चाहते हैं, ये अपनी सच्चाई से डरते हैं, अपने चेहरे से डरते हैं। उपसभाध्यक्ष जी, ये जोशी जी ही थे जिन्होने सीधे-सीधे शिक्षा के क्षेत्र में आर.एस.एस. के एजेंडा को अपने मंत्रालय में निष्ठुरता के साथ लागू करना शुरू किया। उन के आने के साथ ही हमारे देश की शिक्षा और संस्कृति के तमाम प्रतिष्ठित संसाधनो की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाना शुरू हुआ।

उपसभाध्यक्ष जी, हमारे देश में धर्म-निरपेक्ष और बहुलतावादी संस्कृति के खिलाफ अपने संकीर्ण उद्देश्यों का साधने के लिए एक तरह से इन संस्थाओं से चुन चुन कर लोगों को हटाया जाने लगा तथा दूसरी तरफ पाठ्य-पुस्तकों को निहित उद्देश्यो की खातिर बदलने का कार्यक्रम शुरू किया गया। उसी उद्देश्य के तहत एनसीइआरटी के नाम पर, अभी जोशी जी बोल रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सरकार ने आदेश दिया, रात रोए, दिन रोए और उनको कुछ समझ में नहीं आया। मैं यह कह रही थी कि इसी उद्देश्य के तहत एनसीइआरटी के नाम पर, मैं फिर कहना चाहूंगह कि एनसीआरटी के नाम पर, जैसा जोशी जी एनसीआरटी का नाम ले रहे थे, बताएं कि क्या कोई उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई या कोई जनरल बॉडी की मींटिग हुई, जिसमें पाठ्यक्रम पर चर्चा हुई हो। कहीं इसका कोई रिकार्ड नहीं मिलता। एक व्यक्ति, राजपूत जी को लेकर, उनसे मिलकर इन्होने नया पाठ्यक्रम चलाया और पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कहते हैं कि मैंने कहां बदली, पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो हमारे मूलभूत आदर्श थे, हमारे देश की बहुलतवादी संस्कृति की झलक थी, हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता का आदर्श था, उन तमाम चीजों को सिर के बल खड़ा कर दिया और कहते हैं कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार चल रहे थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बदलने का केब (CABE) को अंगूठा दिखाकर, राज्य सरकारों को अंगूठा दिखाकर मनमाने ढंग से एकतरफा निर्णय लिया गया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का विषय जो समवर्ती सूची का विषय हैं, उसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया गया और राज्य सरकारों को नजरअंदाज करके नए पाठ्यक्रमों को शुरू किया गया। जोशी जी कह रहे थे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष जी, आप अभी से सिर हिला रहे हैं, अभी तो मेरी शुरूआत हुई हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): आपके 8 मिनट थे और 11,12 मिनट हो गए हैं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : वे शिक्षा के बारे में कह रहे थे और अपनी पीठ थपथपा रहे थे। जहां तक वाजपेयी जी का हैं, जो उस समय अमरीका में थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हो

रहा हैं। शिक्षा का भगवाकरण नहीं होगा, तो क्या हराकरण होगा? यह रिकॉर्ड में हैं, उपसभाध्यक्ष जी। ...(व्यवधान)... सर, बड़ी मुश्किल हैं, हर चीज में अगर इस तरह टोकाटोकी होगी तो।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोंष बागडोदिया): आप तो बोल सकती हैं, सरला जी।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : कैसे बोल सकती हूं। दिमाग में कंसनट्रेट होना चाहिए विचाराधारा का। ये लोग चाहते नहीं कि मैं बोलूं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहती थी कि किस प्रकार तत्कालीन मंत्री ने केब को मौत की सजा सुनाई, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बिना कोई सलाह-मशविरा किए वे केब, जो कि सबसे उपयुक्त मंच हो सकता था, उपयुक्त मंच हैं कि तमाम राज्य सरकारों की राय ली, उस केब को नजरअंदाज किया गया। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह एक एक करके हमारे देश की शिक्षा, इतिहास, संस्कृति की जो तमाम संस्थाएं थी, चाहे वह आइसीएचआर हो, चाहे वह आइएसएसआर हो, चाहे वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज हो, यूजीसी हो, एनसीइआरटी हो इन तमाम शिक्षा और संस्कृति की श्रेष्ठ संस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। इन सभी संस्थाओं को आरएसएस और भाजपा के विश्वस्त लोगों को सौंप दिया गया। विश्वविद्यालयों में ज्योतिष और ओझागिरी की तरह से कई कोर्स उन्होने शुरू कर दिए, जिसके लिए करोड़ो रूपए का अनुदान दिया गया। वैदिक गणित, वैदिक ज्योतिष, कर्मकांड, वास्तुशास्त्र आदि को विज्ञान का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया):अब आप खत्म कीजिए, प्लीज।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभाध्यक्ष जी, मैं थोड़ा सा समय चाहूंगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया): नहीं, टाइम को देखकर ही मैंने आपसे कहा हैं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : सर, बहुत सारे विषय हैं। तमाम चीजों पर मुझे कहना हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): लेकिन समय जितना एलोटेउ हैं, उतना ही आप बोल सकती हैं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : सर, बार-बार टोकेंगे नहीं, तो मैं जल्दी से जल्दी अपनी बात कहकर समाप्त कर दूंगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया): ठीक हैं, दो मिनट।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : सर, दो मिनट में कुछ नहीं होगा। मुझे जवाब देना हैं, वह जो कह रहे थे। मैं जल्दी जल्दी जवाब देती हूं। जोशी जी कह रहे थे कि कहीं सांप्रदायिकता, कहीं भगवाकरण, कहीं हिंदु मुसिलम वैमनस्य की बात नहीं थी। मेरे पास यह एक किताब हैं- मोडर्न इंडिया, टैक्स्ट बुक फोर क्लास XII, इस किताब में विभिन्न जो चेप्टर हैं, उनके बारे में बता रही हूं।

इसमें एक चैप्टर है, वह चैप्टर हैं 'Cultural Awakening in the Nineteenth Century India', पेज-140 से 141 तक। इस चैप्टर में इन्होने हिंदु स्वराज्यों की बात कहीं

है। इनको एक भी मुस्लिम नाम नहीं मिला जिसके बारे में ये चर्चा करते हैं। यहां तक कि सर सैय्यद का नाम भी 40 पृष्ठों के बाद में दिया गया हैं। उसमें दिया हैं-मुस्लिम पालिटिक्स एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। मुझे समझ में नहीं आता कि मुस्लिम पालिटिक्स, हिंदु पालिटिक्स भी हैं कोई। मतलब मुस्लिम पालिटिक्स का आप नाम लेते हैं यानी वह साम्प्रदायिक हैं। शर्म आती हैं मुझे, हिन्दु महासभा का उल्लेख करते हैं, लेकिन हिन्दु महासभा को एक साम्प्रदायिक संस्था नहीं बताते। सावरकर का नाम लेते हैं लेकिन सावरकर की Two Nation थ्योरी का उल्लेख नहीं करते। ....(व्यवधान)... आप पढ़ते तो हैं नहीं।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): सरला जी, आप इधर बोलिए, उधर मुंह करके क्यों बोल रही हैं। ....(व्यवधान)... सुनिए, अब आपने बहुत समय ले लिया। अब दो मिनट में समाप्त करिए। ...(व्यवधान)... वे यील्ड नहीं कर रही हैं, आप उनको बोलने दीजिए। आप भ्रमित होते रहिए, कोई नुकसान नहीं हैं। ....(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : यह आई.एच.सी.आई. द्वारा निकाली हुई पुस्तक हैं। इन्होने जो पुस्तके शुरू की, उनकी सभी पुस्तकों में इतनी गल्तिंया थी, सिर्फ तथ्यात्मक गल्तियो नहीं वे धाराणाओं की गल्तियां थी कि किस तरह से हिन्दू और मुसलमानों के बीच में वैमनस्य भडकाया जाए, तमाम तरह की विचारधारात्मक जो चीजें थी, उन सबका उल्लेख इन किताबों में किया गया हैं। उनका परसेप्शन देखिए चीजों को समझने का। यह जो किताब हैं सोशल साइंसेज – टेक्स्ट बुक जो माखन लाल की किताब हैं"The discovery of wheel made a significant difference. It was also used to spin cotton and wool, and weaveClothes उस समय यह पहिया कपड़ा बुनने के काम मे आता था कि कितने महान आगे निकले हुए लोग हैं कि समझ में नहीं आता कि इनका क्या परसेप्शन हैं, किस तरह से वे हमारे छात्रों को क्या पढ़ाना चाहते हैं। उपसभाध्यक्ष जी, क्या गुजरात में यह पढ़ा रहे थे। शर्म आती हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसकी चर्चा की। ....(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया): फिर आप उधर बोल रही हैं, इधर बोलिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : जहां हिटलर और मुसोलिनी को गौरवान्वित किया जाए। ...(व्यवधान).. क्या पढ़ा रहे थे गुजरात में। जहां हिटलर और मुसोलिनी को गौरवन्वित किया गया। पार्लियामेंट्री कमेटी ने नोट लिया, "The Parliamentary Standing Committee objections attached with the Union HRD Ministry says there is a 'frighteningly uncritical picture of fascism and Nazism in the io^{h} standard textbook. It says, "The violent, uncivilized and uncritical result of the politics of exclusions of Jews, trade, unionists, migrant labourers, or any पार्लियामेंट्री कमेटी तक ने इसका नोट लिया हैं कि हमारे छात्रों को किस तरह की किताबें पढ़ाई जा रही थी। मुझे अफसोस हैं कि जोशी जी को सुनने का साहस नहीं हुआ, चल गए। आरोप लगाना बहुत आसान हैं। उसके बाद में सुनने की हिम्मत नहीं हैं उनमें। ये क्या पढा रहे थे हमारे छात्रों को।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया): बस, आप अंतिम पोइंट बोल कर खत्म करें।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : किस तरह राजनीतिक उद्देश्यों से भारतीय सभ्यता के प्राचीन इतिहास के तथ्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और हमारी उन संस्थाओं से ऊपर पेशेवर संस्थाओं का नाम ले रहे थे हमारे जय राम रमेश जी। उन पेशागत संस्थाओं का किस तरह दुरूपयोग किया जा रहा था,किन-किन को अनुदान दिया जा रहा था, मालूम हैं आपको ...(व्यवधान)... मालूम हैं तो बताइए। तमाम ऐसे लोगों को जो इस तरह का काम कर रहे थे जो भारतीय सभ्यता के इतिहास को गलत ढंग से रख रहे थे, तमाम ऐसे लोगों के जरिए यह सब काम चल रहे थे। उपसभाध्यक्ष जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जब हमारे शिक्षा राज्य मंत्री कौन सा विज्ञान पढ़ा रहे थे,हमारे शिक्षा राज्य मंत्री, क्या कह रहे थे वे, मैं उनको कोट करना चाहूंगी। - "गले में सर्पो की माला पहन कर जलते हुए अंगारों पर चल कर उन्होने क्या कहा था, भविष्य का विज्ञान हमको सिखा रहे थे। मैं उनको उद्धत करना चाहूंगी कि यह सब भविष्य का विज्ञान हैं और जरूरत इस बात की हैं कि राज्य, मीडिया और समाज इसे प्रोत्साहन दे, मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह रही हूं। मतलब ओझागिरी,जितने अंधविश्वास,जितने पुरातनपंथी धंधे हैं वे सब हमारे समाज में शुरू हो जाएं"।

उपसभाध्यक्ष जी, ये यह भी भूले गये कि कहां से हम आये थे,हम कौन से समाज से थे? ये मार्क्स को उद्धत कर रहे थे, लेकिन इन्होने मार्क्स को पढ़ा नहीं हैं। ...(व्यवधान)... जिस अंध-विश्वास के दौर से,जिस काले ...(व्यवधान)... ऐसे में कैसे बोला जा सकता हैं। ...(व्यवधान)...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, if this continues, then, we also know how to behave in the House. *...(Interruptions)...*

श्रीमती सरला माहेश्वरी : अगर ऐसे किया जायेगा, तो मैं बोल नही सकूंगी। ...(व्यवधान).. ये भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी बातें करते हैं। उपसभाध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि हमेशा साम्प्रदायिक ताकतें संस्कृति की दुहाई देती हैं, क्योंकि उन्हें अपने असली रूप में आते हुए डर लगता हैं। इसीलिए संस्कृति का आवरण पहनकर आती हैं और इन ताकतों को बखूबी प्रेमचन्द जी ने पहचाना हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया) :आप इधर देखकर बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगी कि ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया) **:** अब आप अंतिम पाइंट बोल दीजिये। आपने डबल टाइम ले लिया हैं। ....(व्यवधान)..... देखिये, आपने डबल टाइम ले लिया हैं। ....(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगी कि वह काला दौर अब आप समाप्त हो चुका हैं। हमें भारत की जनता को धन्यवाद देना चाहिए। इस भारत की जनता ने अपनी जनवादी चेतना का, अपनी धर्मनिरपेक्षता चेतना का, अपनी उदारता का ...(व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पणि (उड़ीसा) :उपसभाध्यक्ष जी, यह गलत इंटरप्रटेशन हैं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : आप मुझे बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)... भारत की जनता ने अपनी सहिष्णुता का परिचय देते हुए, इन काली ताकतो को सत्ता के बाहर कर दिया हैं। इसलिए एक नई सरकार सत्ता में आई हैं। मैं उस नई सरकार से कहना चाहती हूं कि भारत की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उन्हे पूरा कीजिए। पिछलें छह वर्ष से जो विवाद चल रहा था,उस विवाद को खत्म करने का समय आ गया हैं। हमारे छात्रों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था, उस खिलवाड़ को बंद करने का समय आया हैं। इसीलिए मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि यह जो कुछ चल रहा हैं इसको तुरंत बंद किया जाना चाहिए। जब हमारे देश के तमाम इतिहासकारों ने लिखित रूप में सरकार के पास इसके बारे में लिख कर भेज दिया था, तो उन्हे इसके लिए पैनल बैठाने की क्या जरूरत थी? मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्यो नहीं आपने उन किताबों को तत्काल बंद किया हैं? आपको कोई पैनल बैठाने की जरूरत नहीं थी। इस पैनल ने भी यही कहा हैं कि तुरंत उन किताबों कों बंद किया जाना चाहिए। फिर भी, जोशी जी कहते हैं कि उनको कुछ नजर नहीं आता हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय अर्जुन सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वह साम्प्रदायिक नजरिये से लिखी हुई, हिंदू-मुस्लिम के बीच मे वैमनस्य बढ़ाने वाली किताबों को पढ़ाना बंद करे। जो किताबें यह कहते हैं कि मुसलमान विदेशी हैं, पारसी विदेश हैं, जो साम्प्रदायिक नजरिया छात्रों के बीच में पैदा करती हैं, उन तमाम किताबों को तत्काल हटाया जाये। इनके शासन के दौरान जो किताबें शुरू की गई हैं, उनकी समीक्षा की जाये,उन सब को तुरंत हटाया जाये। जों किताबों पहले से चल रही थीं, वर्ष 2002 से पहले जो किताबें चल रही थीं, उन किताबों को पढ़ाया जाये। मैं आशा करती हूं कि आप धर्म-निरपेक्षता, जो हमारे संविधान का कूल आदर्श हैं, उस आदर्श की रक्षा करेंगे। आप हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारी बहुलतावादी संसकृति की रक्षा करेगे। इन्ही शब्दो के साथ, मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : उपसभाध्यक्ष जी, मैं तो यह मांग करता हूं कि हर राज्य में जो पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, उनकी जाचं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल, केरल तथा सभी जगह पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों की जाचं और समीक्षा होनी चाहिए। ...(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया)**:** श्री अश्विनी कुमार।

श्री बलबीर के. पुंज : उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। .....(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया)**:** अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछना हैं। ...(व्यवधान)... देखिये, अभी अश्विनी कुमार जी का टाइम हैं। आप उनको बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)... आप क्वेश्चन लिखकर भेज दीजिए। मैं जवाब भिजवा दूंगा ...(व्यवधान)...

SHRI B.J. PANDA (Orissa) : Please give me one minute. *...{Interruptions)...*

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) : Under which rule? ... *{Interruptions)..* .There is no rule. ... *{Interruptions)...* Please sit down. *...{Interruptions)...*Vou cannot do like this. *...{Interruptions)...}* will not accept interruptions. *...(Interruptions)...*This is not fair. *...{Interruptions)...*

Mr. Ashwani Kumar, आप बोलिए। आप हर स्पीकर के बीच में बोलेगे तो कैसे चलेगा? आप बोलिए।

SHRI ASHWANI KUMAR (Punjab): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for according me this opportunity to express my views on a matter of great national importance. Sir, I would like, with your leave, to draw out at the very threshold the contours of this debate. Sir, the contours of this debate can be stretched out in four corners. What are these four corners? Sir, the debate is really about the conscience of our intellectual heritage. It is about a theory of history that claims no absolutes, but, at least, fidelity to facts.

It is also a level, Sir, about the imperatives of respecting the sensitivities of the people in a pluralist society that glorifies its composite culture. Therefore, Sir, this debate is about the philosophy of our Republic. It is about the philosophy of a civilisation in which the distinguished former Minister justly prides himself,, and we share in that pride. Sir, there is a genesis to this debate, and it is a contemporary current genesis. It all started with one principal architect who writing in the *Times of India* talked about the dangers of colonisation of the minds. Of course, he talked about the colonisation of minds in a different context. But I would like to amplify that concept to say that, in a sense, this debate is about an attempt to colonise the minds of the people of the succeeding generations in a particular direction. Now, one may differ with views. People may have a different view about the history books, the curricula, the syllabi, but I may bold to state that in my understanding of the history as written in those books which gave the immediate context for this debate, there is a clear and decisive attempt to colonise the minds of the succeeding generations of India. And, Sir, it is not I who am saying this. It has been brought about in a report which is authored by those who are known for their academic excellence, who are peers in historical research. Sir, one may differ with Mr. Barun De's preferences, ideological preferences, one may differ with his analysis of data of history, but no one in his right mind can reasonably question the academic credentials of the man. I have his credentials, Sir, and I have the sum and substance of the report. Sir, the report summarises its conclusions and says, "We are convinced that the current NCERT textbooks on history brought out after 2000 are substandard and include many errors of fact and also unbalanced interpretation. The errors are so many that rectification of each and every one of them is almost impossible. The problem is further aggravated by directives indicated in the

6.00 p.m.

National Framework for Curriculum in Schools, 2000 which put a premium on indigenous tradition in Indian history identified largely with the ancient Indian values. Later developments in Indian history are seen as irrelevant, if not harmful.' Sir, not a word has been stated in the debate that preceded me to suggest that these conclusions ere either perverse or unsubstantiated. The distinguished former HRD Minister stated that he could find no basis for this conclusion, but, Sir, I only need to point the attention of this House to thirty pages given in Appendix-1 to thif report which have specifically and categorically delineated what the historians consider as 'aberrations' in the writing of history. Sir, in this factual background, the matter, by Public Interest Litigation was brought to the Supreme Court. A lot has been said as to the purport of this Supreme Court judgement, and, Sir, the Supreme Court judgment has been *ad nauseam* misquoted. In fact, Sir, Justice Sinha writing for the Supreme Court said that 'it is true that CABE, an institutional process to oversee everything about educational writing, was not consulted', and it was an institutional process in place from 1935 to 1994.

For sixty long years, without a break, there has been a tradition, a custom, a convention, a practice, of getting the curricula vetted, scrutinized, approved, deliberated upon, by the General Committee of the NCERT, by its Executive Committee and then, by CABE.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

None of these institutions were asked to deliberate, and suddenly, from nowhere, we find that there is a curriculum, which is inflicted on millions of students of History in this country.

Sir, in a liberal tradition of this Republic, which finds mention and endorsement in as sacred a document as the Constitution of India, can we, in that context, not even take steps to rectify the aberrations? I ask myself this question, and I commend this question to the Members of this hon. House - if a particular aberration is specifically pointed out, is it not incumbent on the succeeding Government, which went to the polls on the plea of rectifying the aberrations of history, to correct the distortions of History?

Sir, I lay no claim to an absolute standard of History; no one can. History is always in a state of evolution. History is evolved as societies

evolve, as democracies mature. People give their own imprint to historical processes. Therefore, no one claims absolutes in History. But fidelity to facts from Karl Popper, to E.H. Kar, to Gibon, to Romila Thapar, to A. L. Bashum, to Nizami, to Irfan Habib, has been the tradition. Fidelity to facts is never compromised.

Sir, my respectful submission for consideration of this House, on a matter of grave national importance is, have we prostituted facts, have we suborned facts of history, and have we deliberately done that? It is my guess, and it is the guess of my party. And we went to polls on that guess, and we got a mandate partly on this plea, that there has been a decisive, a conscious distortion of historical facts.

Now, in this context, If the present Minister of Human Resource Development sets up a committee of eminent historians to re-examine the historical books, what is the grave injury that he has done to this great Republic?

Sir, nobody disputes the fact that we have all to be justly proud of our heritage; indeed, we are But what is the heritage that I am proud of? I am proud of my liberal heritage; I am proud of my secular heritage; I am proud of objectivity and intellectual thought; I am proud of a theory of history that taught many, many people of our generation that you cannot consciously misstate facts and suborn historical facts.

Sir, this is the over-arching theme of this debate. In this context, I ask myself this question, is it not true that the highest court in this country, by two judges of the Apex Court, has said that it is undeniable that the institutional processes were suborned and that the discussions that ought to have taken place in the deliberative processes of NCERT and CABE, in fact, were not held?

Sir, in this larger background, I ask myself these questions - 'Is the syllabus a syllabus which needs to be corrected? Are the History books written on the basis of that curriculum required to be corrected or not? And is there anything to suggest that this report, the report prepared by a panel of eminent historians, lacks in objectivity? If the answer to all these questions is in the affirmative, then, we need today to endorse the decision to correct the distortions in History.

Sir, in conclusion, I would only say that it was incumbent, it was necessary, it was politically fair and it was intellectually credible, for this

Government to deliver on the promises it made to the people of India, in whom resides the ultimate sovereignty, through whom the conscience of this country speaks.

We had made a promise to the people of India that we will, on assumption of power, make sure that the attempt for the colonisation of the minds of Indians will be resisted, and we are going to resist it, Sir, with all the force at our command, intellectual, physical and political.

With these words, I thank you for giving me this opportunity.

SHRI S. ANBALAGAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to take part in the short duration discussion, and put forth my views on the change of text books in the school curriculum. It is my bounden duty to express my deep sense of gratitude to the Hon'ble Chief Minister of Tamilnadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma for sending a grass root party worker like me to this August House.

Sir, education is very vital for the development of a nation. Therefore, it is necessary to have excellent curriculum and text books. The centre should assist the State Governments in achieving this task. Since education is the basis for the future of the students, it should not be politicised. Nor should there be an attempt to twist history through text books. Our party is of this firm view on this. When we talk of curriculum and text books, we should not pick and choose a particular period for analysis. A lot is being said about the attempts by the centre to change history texts and also the curriculum too often. We fail to remember the root cause of all these problems.

It all began in the year 1976. The then Congress Government shifted education from the state list to concurrent list. It is this concentration of power with the Union Government that paved the way for making arbitrary decisions. In the recent years we have been hearing about rewriting history. Of course, it would not be in the interest of the nation to distort history. AIADMK party, that I am wedded to, is of the firm opinion on this. But I would like to ask the Government, whether the history that has been taught to us is a witness to truth? With a sense of deep anguish I wish to tell the House that a number of great freedom fighters from Tamilnadu do not find a mention in our freedom history. All their names have been blacked out. The great fighter Veerapandia Kattampomman, the brave brothers Chinna Maruthu-Peria Maruthu, the Jhansi Rani of Tamilnadu Velu Naichiar, the woman warrior Thillaiyadi Valliammai and the brave patriot Theeran

Chinnamali are some of the names that are not even mentioned in Indian History. The Government owes a duty to tell us why they are not mentioned in our history. When I say this I am reminded of the great leader of the Dravidian movement Peraringnar Anna who, once said on the floor of this very Hosue, 'North Flourishes, but South perishes' I hope the 12 Ministers who are in the UPA Government will take steps to rectify this error.

Sir, when we talk of education we have to refer to our education policy. What happened to the National educational policy announced by the Congress in 1986? According to that policy, by the year 1990 all the children should have completed 5 years of schooling by the age of 11 and by the year 1995, all children were to be given free education until the age of 14 years. But all these promises were thrown to the winds later.

Language is the basis for education. But what is our policy on the language issue? I think even many Ministers do not know this. This is the fact. The late Prime Minister Pt. Jawahar Lai Nehru gave an assurance that Hindi would not be imposed on the non-Hindi states. I don't think his assurance is being honoured. I must make one thing clear here. Neither we are enamoured of English nor are we opposed to Hindi. We only want the people to learn in their mother tongue in the language of the respective State.

Sir, from the year 1986 injustice is being done to candidates seeking employment in Kendriya Vidhyalayas. From drawing master to English teacher, the knowledge of one particular language is sought to be essential. Now I request that all State languages, like Tamil, Malayalm, Kannada and Telugu should be included in this. I say this because, I am myself a teacher and many teachers have discussed this with me. Sir, I wish to point out an aspect of various educational schemes *(time bell).*

Mr. Vice Chairman, Sir, as this is my maiden speech, I request you to allow me a little more time.

Sir, even the schemes are named in one particular language. The names of the schemes like Bhartiya Shisksha Kosh, Sarve Shiksha Abhiyan and so on. These names are not understood by anybody in many States. The Government should try to name the schemes in other languages as well.

At this point I wish to make a reference to Tamilnadu. Tamilnadu has set an example in formulating education policy. In the benign rule of Dr.

Puratchi Thalaivi Amma, Tamil Nadu Government has launched a website for the Education Department. And that web site opens with a couplet from Thirukural, the holybook of Tamils, a grand treatise on high morals. The couplet goes:

In sandy soil when deep you delve, you reach the stream below,
The more you learn the freer stream of wisdom flow.

Anyone, either from Tamil Nadu or Delhi or even abroad could send suggestions to the Government and worthy suggestions are considered. Tamil Nadu is an example of how a secular and culturally compatible curriculum for the school could be prepared. We had so far only three aspects of study; prose; music and drama. But now, for the first time in India, Tamil Nadu has added one more aspect, that is scientific Tamil. This is being introduced from class I in Tamil Nadu. I think the Centre could take steps to introduce it in other States as well. Environmental awareness is also introduced to educate the children of our surroundings. So also there is aids-awareness education that could be introduced as precautionary measure. English is also introduced from first standard so that students can compete in the global market. Happily, India is a lead player in the WTO regime. That is why China has now woken up to teach English to their students. China wants to develop in the area of software industry. Going a step ahead, Tamil Nadu has introduced bio-chemistry, Dietetics and Nutrition, microbiology and English for communication in higher secondary schools. These subjects were so far the exclusive domain of the college curriculum. Special coaching is given to SC/ST students in Tamil Nadu. The SC/ST girl students are given free bicycles for attending school.

From this year, free cycles are given to BC, MBC and Denotified community students as well. During the last three years, 1,54,410 students have received the benefit at a cost of 22 crore rupees. This year at a cost of Rs. 8 crore 8,50,50,000 students received the benefit. At a cost of 47 crore rupees, 29.600 MBC girl students received the benefit.

Sir, I wish to make a few short points. While discussing curriculum and text books, parents and the public should also be involved. This will be helpful in formulating the curriculum.

The Centre should consult The States while formulating the education policy in the future. I hope the Government will bear this in mind. I thank you, Sir, once again and conclude.

डा. कुमकुम राय (बिहार): धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय।

श्री उपसभापति : आप की पार्टी के 5 मिनट हैं।

डा. कुमकुम राय **:** महोदय, बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही हैं। हम लोगों ने आज तक यह जाना था कि शिक्षा हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती हैं, असत्य से सत्य की ओर ले जाती हैं और मृत्यु से अमृता की ओर ले जाती हैं। किन्तु इस हिंदुस्तान में इस बात का हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री ने गलत साबित कर के दिखलाया और उन्होंने शिक्षा को औजार बनाने का प्रयास किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के छिपे हुए एजेंटे को लागू करने के लिए उन्होने शिक्षा को औजार बनाया, यह बात भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गयी हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष एक धर्म-निरपेक्ष गणराज्य हैं। इसलिए संविधान के निर्माताओं ने सदियों पुरानी गंगा-जमुनी संस्कृति की विरासत का सम्मान करते हुए संविधान की प्रस्तावना में ही धर्म-निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया था। और 15 अगस्त,1947 को हम आजाद हुए, हालांकि विभाजन का दंश हमें सहना पड़ा , किनतु स्वतंत्र हिन्दुसतान में अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय, अनेक जातियों के लोगों को एक समान नागरिक माना गया। आरंभ से हम स्कूलों में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के बारे में जाने-माने इतिहासकारों के द्वारा स्थापित तथ्यो को पढ़ते रहे, लेकिन एनडीए की सरकार जब बनी तो हमारे तत्कालीन मंत्री जी ने वर्ष 2000 में एनसीइआरटी की स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाई और उस रूपरेखा के बहाने से उन्होने उसे नई पाठ्यपुस्तको में लाने के लिए एक मजबूत इरादा बना लिया और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता रमेश जी ने भी कहा, इसमें एनसीइआरटी की तमाम जो प्रक्रियाएं थी, उसका उन्होने पालन नही किया, सरला जी ने भी यही बात कहीं कि उसकी किसी प्रक्रिया का उन्होने पालन नही किया। आपके द्वारा बार-बार यही दुहाई दी जाती रही कि जो पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में रही थी उसके नियमों और नीति के तहत हमने समीखा की हैं। अगर आपने समीक्षा की, तो यह कैसे परामर्श हुआ, जिसमें हमारे देश के प्रसिद्ध और विद्धान इतिहासकारों के परामर्शो का कोई जिक्र नही आया? क्यो उन्हे कोई तरजीह नही मिली?

उपसभापति महोदय, हमारे देश ने अनेक सुविख्यात इतिहासकारों ने पिछली दिनों यह मांग उठाई और यह मांग कोई अचानक नहीं उठाई गई, पिछले 6 वर्षो में चारो तरफ से यह बात उठने लगी थी कि किस प्रकार एनसीइआरटी के नाम पर इन्होने देश की संपदा, देश की बौद्धिक संपदा को प्रदूषित करने का एक घिनौना काम करना शुरू किया था। उस समय से चली आ रही मांग को देखते हुए जैसे ही हमारी यह नई सरकार बनी, हमारे तमाम विद्धान इतिहासकारों ने पुनः मांग उठाई, जनता की तरफ से आवाज उठी, स्वंय अभिभावको ने यह मांग उठाई कि एनसीइआरटी के द्वारा प्रकाशित इतिहास का मौजूदा जो स्कूली पाठ्यक्रम हैं, उसको तुरन्त अकादिमिक सत्र से हटा लिया जाए क्योंकि यह हमारे हिंदुस्तान में, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि इस देश में विभिन्न भाषा, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, इनके बीच में विभाजन की रेखा पैदा करता हैं और हम लोगों के बीच में इस प्रकार की दीवारें खड़ी करता हैं। किसी धर्म और संप्रदाय को कम करके आंकना और अपनी-अपनी बात को उच्चता और वर्चस्व के रूप में कहने की इनकी प्रवृत्ति को लोगों ने महसूस किया और अपनी मांग को रखा, इन्ही मांगों की बदौलत हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री ने सुप्रसिद्ध और तटस्थ, मैं कहना चाहूंगी कि

तटस्थ मान्यता प्राप्त इतिहासकारो का एक पैनल बनाया। मैं इसकी विस्तार से चर्चा नही करना चाहती, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि वे इतिहासकार उन इतिहास की पुस्तकों की समीक्षा करते समय कहीं भी, कोई भी साप्रदायिक अंश नहीं पकड़ पाए, कोई भी भगवाकरण करने वाला अंश नहीं पकड़ पाए और वे कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं प्रापत कर सके, इसलिए उन किताबों को हटाने की क्या जरूरत हैं? तो मैं कहना चाहता हूं –

सिर से सीने में कहां, पेट से पांव में कहां,
एक जगह हो तो कहें, दर्द किधर होता हैं?

उपसभापति महोदय, इसलिए हमारे उन विद्वान इतिहासकारों ने कहा कि इन किताबों दुरूस्त नहीं किया जा सकता हैं, उसमें कहां-कहां पैबंद लगाए जाएंगे, पूरी की पूरी किताब ऐसी हैं। यहां मैं आपको बताना चाहती हूं कि चूंकि ये किताबे सांप्रदायिक विचारधारा से ओतप्रोत होकर के ऐसे ताने-बाने से और हिंदुत्व का संदेश देने के लिए बुनी गई थीं, जिसे राष्ट्रवादी, राष्ट्रीय-प्रेम, भारतीयता का नाम तक दिया गया, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती और यही कारण हैं कि पैनल की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि इन किताबों को दुरूस्त नहीं किया जा सकता हैं, इसलिए ये पूरी किताबें हटा देनी चाहिएं। हमारे शिक्षा मंत्री ने बहुत अच्छा काम किया और हमारे शिक्षकों की उस तकलीफ को देखते हुए उन्होने यह निर्णय लिया कि इस अकादिमिक सत्र से ये किताबें नहीं हटाई जाएंगी, लेकिन यह जरूर प्रमाणित हुआ हैं कि उनका पुनर्लेखन आवश्यक हो गया हैं और इसलिए किताबों का पुनर्लेखन होना चाहिए।

उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, फातमी साहब यहां बैठे हुए हैं, यह मांग करना चाहती हूं कि जिस तरह हमारे पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री ने ओझागुनी, डाइन जोगिन और इस प्रकार झाड-फूंक के सिंद्धात को बढ़ावा देने के लिए उसको भी शिक्षा में शमिल करने की बात की थी।

हमारे यहां वैदिक गणित, ज्योतिष,धर्मकांड पुरोहित इनको भी पढ़ाने की बात की गई थी और विश्वविद्यालय की भी स्वायत्तता पर अब कुठाराघात किया जाने लगा था, निजीकरण की बात की जाने लगी थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि यदि सरकार की तरफ से कोई भी पुस्तक लिखी जाती हैं या लिखवाई जाती है संस्था के माध्यम से तो इसकी व्यापक पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि देश की जनता को विश्वास हो सके कि उसके बच्चे, आगे आने वाली पीढ़ी, एक सही इतिहास की जानकारी ले सकें। इन्ही शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती मोहसिना किदवई (छत्तीसगढ़): माननीय उपसभापति जी, मैं आपकी बहुत मश्कूर हूं कि आपने मुझे बोलने का वक्त दिया। बड़े ही अहम मौजू पर यह बहस हो रही है। लेकिन मैं समझती हूं कि इसके लिए वक्त बहुत कम हैं। इतने कम समय में जितमना कुछ कहा जाना चाहिए वह कहा नहीं जा सकता। मुरली मनोहर जोशी जी का भाषण बड़े गौर से सुन रही थी। वैसे वे इस समय हाउस में नहीं हैं। लेकिन उन्होने इतनी मासूमियत से अपना भाषण दिया, इतना इन्नोयेटली अपना भाषण किया कि लगता हैं कि उन्होने कुछ किया ही नहीं हैं, लगता हैं कि जो कुछ भी उनकी सरकार ने या खुद मुरली मनोहर जोशी ने किया वह कोई गलत बात नही, बल्कि गलत बात जो की जा रही हैं, वह अब की जा रही हैं कि जो जहर उन किताबों

में भरा हुआ हैं अगर उसको निकालने का काम किया जा रहा हैं तो वह उनको निकालने का काम किया जा रहा हैं तो वह उनको अच्छा नहीं लग रहा हैं। उपसभापति महोदय, मैं आपसे बाअदब यह दरख्वास्त करना चाहती हूं कि बच्चो की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। किसी भी देश का इतिहास इस पर निर्भर होता हैं कि उस देश की एजुकेशन पालिसी क्या हैं और मैं समझती हूं कि एजुकेशन ही एक सबसे बड़ी जरूरी बुनियादी चीज हैं कि जिससे एक अच्छे इंसान को बनाया जा सकता हैं। जैसे हीरा होता हैं, पत्थर होता हैं। जितनी अच्छी तरास-खरास जिस हीरे की होगी, वह उतना ही कीमती होता हैं। यह भी इसी तरह से हैं कि यदि हमारी बुनियादी तालीम अच्छे ढंग से हो जाए, तो फिर वह अच्छा इंसान बनता हैं और मैं समझती हूं कि आज इस देश का जो विद्वान तबका हैं, जो पालिटिकल तबका हैं, उसको यह सोचने की बात हैं कि किस तरह से इस देश की एजुकेशन पालिसी को लागू किया जाए और किस तरह से इस देश की आने वाली नस्लों को एक अच्छा इंसान बनाकर पैदा कियर जा सके। जहां तक सवाल मुरली मनोहर जोशी जी के भाषण का हैं, उन्होने जिस तरह से एक अपना व्यू पोइंट रखा, मैं समझती हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो यह कहा जाए- क्योंकि यहां पहजी बार बहस नही हो रही हैं, अभी जब उनकी सरकार थी तो लोक सभी में भी बहस हुई थी और काफी देर तक दिन भर वह बहस चली थी और सारे लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था। उसमें कांग्रेस प्रेजीडेंट श्रीमती सोनिया गांधी ने जिस तरह से अपने भाषण में दो-चार जुमलों में साफ कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी का या उनकी पार्टी का या और सेक्युलर फॉर्सेज का इसमें क्या हिस्सा रहेगा और उन्होने कहा था जिसे मैं कोट करती हूं

तो यह और उसके अलावा जितने लोगों ने भाषण दिया, इस समय वक्त नही हैं कि मैं बताऊं कि लोगों ने क्या-क्या कहा। लेकिन जहां तक एन.सी.ई.आर.टी. का मसला हैं, इतनी वैल रिप्यूटिड, इतने रेस्पेक्टेबल ये सारे इदारे थे, लेकिन मुझे अफसोस है कि पिछली सरकार ने उनकी जो सारी इमेज थी, जो रेस्पेक्टेबिलिटी थी, वह सब खत्म कर दी। कोई दूसरे इदारे यह बात करें तो उसको एक बार माफ किया जा सकता हैं लेकिन गवर्नमेंट के वे इदारे, वे इंस्टीट्यूशन, जिनकी इस चीज के लिए जिम्मेदारी थी और अगर उनके जरिए यह बात होती हैं और इस तरह से टेक्स्ट बुक्स बदली जाती हैं तो मैं समझती हूं कि उसका बहुत बुरा असर पूरे देश में पड़ता हैं। देखा यह जाता हैं कि सरकार जो काम कर रही हैं, उसके पीछे उसकी नीयत क्या हैं। अगर नीयत अच्छी होती तो मैं पूछना चाहती हूं मुरली मनोहर जोशी जी से जो उस वक्त मिनिस्टर थे, तो अगर उनकी नीयत साफ होती तो उसके ऊपर कितना वाइड डिस्कसन करना चाहिए था इंटलेक्च्युअल्ज से, हिस्टोरियंस से, जितने लोग उससे संबंधित हैं उनसे, मैं मिसाल दूंगी कि 1986 में राजीव गांधी जी ने जो नई पालिसी बनाई, उसको बनाने की कोशिश की तो 8-10 महीने तक व्यापक रूप से उस पर डिस्कन हुआ। क्योंकि यह कोई मामूली बच्चो का खेल नही हैं कि आज आप पालिसी बनाइये और कल उसे बिगाड दीजिए। उस पालिसी को बनाने में काफी वक्त लगा, लेकिन डा. मुरली मनोहर जोशी जी की सरकार को, उनके डिपार्टमेंटे को, सारी टैक्स्ट बुक्स को बदलने में कोई वक्त नही लगा। उसके लिए ...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति : वे बोल रही हैं। आप बीच में कमेंट्स मत कीजिए।...(व्यवधान)...

श्रीमती मोहसिना किदवई :उपसभापति महोदय, मैं थोड़ा-सा पढ़ना चाहती हूं,

'The NCERT had no ulterior motive in choosing to be silent on the assassination of Mahatma Gandhi in a new text-book is hard to believe. Is it because of Nathu Ram Godse's RSS background? It is the omission and commission of this kind that compelled 16 State Education Ministers to reject the new curriculum.'

अगर आपने पहले बहस की होती, तो हम यह हश्र नहीं होता। दूसरी बात, मैं यह साफ कहना चाहती हूं। हमारे अर्जुन सिंह जी, मानव संसाधन मंत्री जी आरएसएस की बात कह रहे थे। आरएसएस वह जमात हैं जिसने टू नेशन थ्यौरी ....(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप बीच में मत टोकिये। ...(व्यवधान)...

श्रीमती मोहसिना किदवई : आप जरा सुनने की हिम्मत रखिये। ...(व्यवधान).. मैं यील्ड नहीं कर रही हूं। ....(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : वह अनपार्लियामेंट्री कुछ नहीं कह रही हैं। ...(व्यवधान)... देखिये, उनको अपने विचार रखने का हक हैं। ...(व्यवधान)... जब आपका बोलने का समय आयेगा तब आप बोलिये। ...(व्यवधान)... वह यील्ड नहीं कर रही हैं। ...(व्यवधान)..

श्रीमती मोहसिना किदवई :मैं यील्ड नहीं कर रही हूं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : प्लीज, आप बैठ जाइये। ये उनके विचार हैं। ...(व्यवधान)... वे क्या आपके विचार बोलेंगी।...(व्यवधान)..

श्रीमती सविता शारदा (गुजरात): उपसभापति महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति :वे अपने विचार व्यक्त कर रही हैं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती मोहसिना किदवई :उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूं ...(व्यवधान)...

श्री बलबीर के. पुंज :उपसभापति महोदय,....(व्यवधान)...

श्रीमती मोहसिना किदवई : मैं आपको बता रही हूं। ...(व्यवधान)... मैं आपको सुना रही हूं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : वे यील्ड नहीं कर रही हैं। ...(व्यवधान)... आप उनको अपने विचार रखने दीजिए। ...(व्यवधान)... आप अपने विचार रखियेगा। ...(व्यवधान)... यह कोई तरीका नहीं हैं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती मोहसिना किदवई : उन्हें हाउस की मर्यादा का पता नही हैं। उपसभापति जी, मैं आपसे कह रही थी। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति :मेडन स्पीच में कोई इंटरेप्ट नहीं करता हैं। आप इंटरेप्ट कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

* **श्रीमती मोहसिना किदवई :** उपसभापति जी,...(व्यवधान).... "The RSS Chief, K. Sudarshan, today said here that the HRD Minister, Dr. Murli Manohar Joshi has given the country's education a cultural perspective, which is exactly what the Sangh wanted. The RSS Chief, without mincing words, said that Joshi has achieved what the RSS had been fighting for the last 50 years."

SHRI BALBIR K. PUNJ: Mr. Deputy Chairman, Sir, the hon'ble new Member should be told that she should not mention the names of those persons who are not present here.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Who is not present in the House? He is a Member of this House.

SHRI BALBIR K. PUNJ: It has been the convention here that we do not mention the names of those persons who are not here to defend themselves.

श्री उपसभापति : यह क्या तरीका हैं? आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)...

SHRI BALBIR K. PUNJ: She has mentioned the name. *..(Interruptions)...*

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: No, no. I am reading from somewhere.

SHRI BALBIR K. PUNJ: Sir, the hon. Member should be told that we do not mention the names of those persons who are not present in the House. *.(Interruptions)...*

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: But I am reading from somewhere. I am not taking the name. मैं आपसे यह कह रही थी कि ये सारी चीजें जो हैं, ये चीजें सरकार की नीयत को दर्शाती हैं। मुझे मालूम हैं कि आप बार-बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं। मेरी मेडन स्पीच है फिर भी मैं आपसे यह नही कहूंगी कि मुझे ज्यादा वक्त दें। ....(व्यवधान)...

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) :उपसभापति महोदय, माननीय सदस्या की मेडन स्पीच हैं इसलिए इसमें दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पणि :यह नियम हमको बता रहे हैं, यह नियम उनको बताना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप बताने के बाद कि उनकी मेडन स्पीच हैं, फिर भी इंटरेप्ट करते । यह क्या बात हैं? ...(व्यवधान)...

श्री बलबीर के. पुंज : उपसभापति महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : यह ठीक नहीं हैं। ....(व्यवधान).... प्लीज यह ठीक नहीं हैं। ...(व्यवधान)....

श्री मोहसिना किदवई :उपसभापति जी, मैं यह कह रही थी कि इस देश की गंगा-जमुनी तहजीब हैं। यह ऐसा देश हैं जहां अकसरियत और अकसारित का कहीं अंदाजा नहीं कर सकते। नार्थ-ईस्ट में चले जाइये, तो वहां ईसाई बहुमत में हैं, अगर श्रीनगर में चले जाइये, तो वहां मुस्लिम बहुमत मे हैं, उससे जरा नीचे आइये पंजाब में तो हमारे सिख भाई बहुमत में हैं और बाकी में हमारे हिन्दु भाई हैं। यह मिली-जुली एक गंगा-जमुनी तहजीब हैं। अगर टू नेशन थ्यौरी देश में लागू होगी, तो क्या देश पनप पायेगा?

आज मुझे लगता हैं कि एजुकेशन के जरिए हम एक हैल्दी एटमोस्फेयर बना सकते हैं, एक हैल्दी दिमाग बना सकते हैं। मैं समझती हूं कि अच्छी तालीम का मतलब यह नहीं हैं कि हम डिग्रियां हासिल करें। अच्छी तालीम का मतलब एक विशाल ह्दय, एक-दूसरे के व्यू-प्वाइंट्स को समझने की सहन शाक्ति एक-दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहने की बात हैं। और यह देश, इसको आप इस तरह से नहीं देख सकते हैं। जो आपके तमाम स्कूल कहते हैं कि हमारी कुछ कल्चरल संस्थाएं हैं और वे कल्चरल संस्थाएं जिस किस्म की एजुकेश्नल इंस्टीट्यूशन्स चला रही हैं,मैं समझती हूं कि वह इस देश के लिए बहुत घातक चीज हैं। इसमें इतनी ज्यादा गुंजाइश बहस करने की, बात करने की हैं लेकिन मैं आपसे केवल एक बात और कहना चाहती हूं कि आज इस देश को एक स्ट्रॉग विजन की जरूरत हैं। कौन ऐसा हिन्दुस्तान होगा जिसको अपने देश पर गर्व न हो? लेकिन आज जिस तरह की नीतिंया कुछ पार्टीयां चल रही हैं, उन नीतियों के जरिए इस देश में जो अलगाव और बिखराव पैदा हो रहा हैं,समाज को तोड़ने की बाते हो रही हैं, क्या वे देश को ताकतवर बना रही हैं? आज नेहरू जी का एक कोटेशन हमारे मुरली मनोहर जी ने बताया। जहां उनको जरूरत हैं, उन्होनें कोटेशन दी। उनको एक कोटेशन और नेहरू जी का देना चाहिए था। नेहरू जी ने कहा था कि इस देश में मजहब की आजादी सबको हैं। जो मजहब चाहे, जिस तरह से तरीका-ए-इबादत चाहे, करे, तो मजहब चाहे वह ज्वाइन करे लेकिन इस देश में किसी को यह आजादी नहीं दी जा सकती कि वह मजहब के नाम पर इस देश को तोड़ने की कोशिश करे। यह वह कोटेशन हैं जिससे आज हमे सबक हासिल करना चाहिए। आज इस देश में एक रूझान हैं कि किस तरफ से हमारी पढ़ाई का सवाल हैं, क्या हमारी शिक्षा नीति होनी चाहिए, क्या हमारी टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए। अगर ये सारी किताबे बदलने की बात थी, तो उसका एक तरीका था। तमाम ऐसे इदारे हैं जो आपके साथ आपकी मदद करते, लेकिन उसमें आपकी बदनियती थी क्योंकि आप एक खास लाइन पर एजुकेशन को चलाना चाहते थे। उसकी इजाजत इस देश में नहीं दी जा सकती। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह दरख्वास्त करूंगी, पुरजोर दरख्वास्त करूंगी कि ऐसी सारी किताबों के लिए वे भी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं – पैनल्स बनाएं, मुख्तालिफ पैनल्स बनाएं और कोशिश करे कि उसमें ज्यादा से ज्यादा दखलअंदाजी पॉलिटिकल लोगों की न हो। उसमें इंटलेक्चुअल्स की पढ़े-लिखे लोगों की, हिस्टोरियन्स की सलाह ली जाए। यह हिस्टरी कोई आज के दिन नहीं लिखी जा रही हैं, कोई आज के लिए काफी नहीं हुई हैं। देश अपनी हिस्टरी पर चलते हैं, अपनी तारीख और उनकी हिस्टरी उनकी पहचान होती हैं, इसलिए मैं आपके जरिए मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आज लोगों को आपसे बहुत आशाएं हैं। ऐसा करिए कि आने वाली नस्ले उस चीज से प्रभावित न हो, जिसको यह देश सहार नहीं

सकता। इस देश में सब मिल-जुलकर एकता के साथ ही आगे चल सकते हैं और मैं समझती हूं कि इसके लिए सबसे बड़ा माध्यम हमारी एजुकेशन पॉलिसी हैं।इसलिए उसको बहुत सोच-समझकर और गंभीरता के साथ लेना चाहिए। मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगी, उधर बैठने वाले लोगों से, कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, हमारी और आपकी, दोनो की जिम्मेदारी इस देश को चलाने की हैं और आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़कर जाने की हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगी कि उसको बहुत गंभीरता के साथ ले। जिससे भी मदद लेनी हो, ले लेकिन एक ऐसी शिक्षा की पॉलिसी हो जो अच्छे इंसान पैदा कर, जिनकी संकीर्ण विचारधारा न हो, जिनका खुला दिल और दिमाग हो,जिनकी सोच, जिनकी विजन हो, वे इस देश के लिए सोच सके, इस मुल्क के लिए सोच सकें और सबसे बड़ी बात यह हैं कि इस मुल्क की एकता के लिए वे सोच सकें।

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह (बिहार): उपसभापति महोदय, आज एक दिलचस्प, रोचक और अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल पर विचार हो रहा हैं। कई सवालो पर लगता हैं कि दोनो ओर सहमति भी हैं। अभी हमारी पूर्व वक्ता ने मंत्री जी को बधाई दी और मंत्री जी से आग्रह किया कि ऐसी शिक्षा नीति बने जो देश के हित में, देश की परिस्थिति और देश की आवश्यकता के अनुरूप हो। महोदय, आपको भी मालूम हैं और सारे सदन के सदस्यो को भी मालूम हैं कि इतिहास लेखन पर बहुत पहले से, बरसो से विवाद रहा हैं। उस विवाद से कोई इंकार भी नहीं कर सकता। इतिहास-लेखन इतिहासज्ञो पर निर्भर करता हैं कि इतिहास की घटनाओं का वे किस ढंग से व्याख्या का काम करे। एक घटना का मैं उदाहरण देना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि उस पुस्तक को यदि सदन में रख दिया जाए, तो अभी सत्ताधारी दल में शामिल जो घटक हैं, उनकी भी उस पर सहमति होना बहुत ही मुश्किल हैं। जयप्रकाश नारायण जी का एक बड़ा मूवमेंट इस देश में हुआ। जयप्रकाश नारयण के मूवमेंट पर कोई यदि इतिहासज्ञ लिखे और वह देश का reknowned इतिहासज्ञ हों, और वह एस पर अपने angle से, उस आंदोलन की व्याख्या कर दे, तो हजारो-लाखों लोग, जो उस आंदोलन मे शरीक थे और सैकड़ो और हजारो की संख्या में जो साहित्यकार और दूसरे कवि आदि शामिल थे, उनके सेटिमेंटसं पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इतिहास का डिस्टॉर्शन इसी ढग से होता हैं। मुझे एक ही बात कहनी हैं और मैं मंत्री जी से आलोचना के स्वर में नही, केवल सुझाव के स्वर में कहना चाहता हूं कि इतनी जल्दबाजी क्या हैं? यदि विचार के आधार पर पाठ्य-पुस्तकों के अंदर परिवर्तन करने की बात की जाए और यदि राजनीति इसमें आ जाए, तो पाठ्य-पुस्तको के परिवर्तन को कभी लाजमी, न्यायसंगत और तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। चार महीने की अवधि में इतनी जल्दबाजी में इन पाठ्य पुस्तकों के पाठ्यक्रम मे परिवर्तन कर दिया जाए? व्यापक पैमाने पर बहस को ले जाना चाहिए था। परिवर्तन केवल इतिहास और सामजिक विज्ञान के पुस्तकों में ही क्यों किया गया? मैं उन सारे विद्वानों पर,ग्रेवाल साहब पर, वरूण जी पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता, न उनकी विद्वता के ऊपर मैं कोई प्रश्नचिन्ह खड़ा करना चाहता हूं लेकिन चाहिए था कि जो तमाम पाठ्य-पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, उनको एक नए सिरे से देखने का प्रयास किया जाता और आपत्तिजनक अंशो पर बड़े पैमाने पर विचार होता, तो शायद और अच्छी पाठ्य-पुस्तकें निकल सकती थीं। लेकिन एक खास विचारधारा से ये अंश आपत्तिजनक हैं और इन्हीं को निकालने के लिए यदि राजनीति को इसमे लाया जाए, तो कभी भी शिक्षा विभाग के साथ न्याय नहीं हो सकता हैं। हमको लगता हैं कि मंत्री जी ने कुछ जल्दबाजी की हैं। यदि मंत्री जी को करना है तो पाठ्य पुस्तकों में केवल आपत्ति वाले अंश ही क्यो रखे जाएं, बल्कि पाठ्य-

पुस्तकों में देश की नई आवश्यकताओं के अनुरूप भी और क्या-क्या डाला जा सकता हैं, उस पर विचार करने की जरूरत आज आ गई हैं। स्वदेशी, स्वावलम्बन की प्रवृत्ति जगाने वाली बातों को पाठ्यक्रम में क्यों नहीं लाया गया? यदि अंधविश्वास के ऊपर प्रहार करने की बात हो और पाठ्यपुस्तकों में उन अंशों को क्यों नहीं रखा जाएगा? इन सारी चीजों की आज जरूरत हैं?

उपसभापति महोदय, क्या इस देश में राष्ट्रपति पदक, पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की कमी हैं? उनके बीच में या लेखन का कार्य करते हैं, उनके बीच मे वे बहस को ले जाते, राष्ट्रीय स्तर पर बहस होती, बहस के बाद कुछ बिंदु तैयार हो जाने, उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी बैठाई जाती और एक-डेढ़ बरस के अंदर शिक्षा नीति मे परिवर्तन करने की बात होती,पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की बात होती, तो शायद इस कदम को ज्यादा व्यावहारिक, ज्यादा तार्किक तथा ज्यादा न्यायसंगत कहा जा सकता था, लेकिन सरकार आई, और लगता हैं कि हड़बड़ी में कुछ ऐसी चीज आ गई हैं गई हैं कि यदि इन बातों को,इन अंशो का हटाया नहीं गया तो हमारी छाप वोट की दृष्टि से अच्छी नहीं बन सकती, हमारी छाप राजनीतिक दृष्टि से अच्छी नहीं बन सकती हैं। उस किताब को मैं अभी लाया नहीं हूं, जयप्रकाश नारायण के बारे में जो लिखा गया था। यदि लाता तो शायद लालू जी को बहुत आपत्ति हो सकती थी, जो आज इस सरकार में शमिल हैं क्योंकि वे भी एक मंत्री हैं। वे कभी कबूल नहीं करेंगे कि जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट का मूल्याकंन इस ढंग से किया जाए। एक उदाहरण के तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं। मैं मंत्री जी से यही आग्रह करना चाहता हूं कि यदि परिवर्तन करना हैं इसको,तो इस पर व्यापक बहस चलाने का काम कीजिए।

उपसभापति महोदय, धर्मनिरपेक्षता पर भी आज कोई बहस हो सकती हैं क्या? उसकी सैंक्टिटी पर भी कोई बहस हो सकती हैं क्या? कई ऐसे सवाल हैं। जिस पर राष्ट्रीय सहमति बन चुकी हैं, केवल राजनीतिक की दृष्टि से उस पर बहस की जाए, यह कतई उचित नहीं हैं। मैं यह मांग करता हूं कि केवल इन्ही अंशों को नहीं, सारे पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण करने के लिए, उसकी जाचं करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए। उस पर बड़े स्तर पर बहस चलाई जाएं तभी हम इसमें परिवर्तन करेंगे तो अच्छी बात हो सकती हैं।यदि रूप में शुरूआत की जाए तो केवल विचार को पुष्ट करने के लिए नहीं, राजनीति को प्रसारित करने के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा को व्यावहारिक बनाने के लिए, शिक्षा को उपयोग बनाने के लिए शिक्षा को जनता के बीच में ले जाने के लिए, शिक्षा को निर्धनता रेखा के नीचे रहने वालो बच्चो के बीच अच्छे ढंग से ले जाने के लिए शिक्षा नीति बन सकती हैं, आज वहीं जगह व्याहारिक हो सकती हैं। रचना और संस्कृति के इतिहास में महात्मा फुले को कौन भूल सकता हैं।इस इतिहास में अम्बेडकर और दयानन्द सरस्वती ने जो कुछ किया, उसको इतिहास कैसे अनदेखा कर सकता हैं? महात्मा गांधी, बुद्ध और अशोक ने जो कुछ किया हैं, इसमें भी कहीं साम्प्रदायिकता की बू किसी को दिखाई पड़ती है तो सोचने के तौर-तरीके में कुछ आपत्ति हो सकती हैं, कुछ विरोध के स्वर दिखाई पड़ सकते हैं। इसीलिए मेरा आग्रह हैं कि इतिहास के जो स्वार्णिम अध्याय हैं, इतिहास के जो गौरवशाली पन्ने हैं, उनके साथ छेड़-छाड़ करने का मतलब, अपने साथ छेड़-छाड़ करना होगा। उन पन्नों के साथ छेड़-छाड़ करने का मतलब, देश के इतिहास और देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना होगा। संस्कृति की परिभाषा में, अपने-अपने ढंग से व्याख्या करने की हम बात कर सकते हैं। हम कट्टरवादी तत्वों की बात करते हैं। अधिकांशं पार्टियों ने जगह-जगह समझौता किया हैं। उसके बाद भी हम सैक्युलर बने रहते हैं। देश के अधिकांशतः विद्धानों की

शिक्षा नीति के बारे में एक ऐसी पॉलिसी बने जिसमें पाठ्यक्रमों पर कोई आपत्ति नजर नहीं आए। उस पर कोई दूसरे ढंग का आब्जेक्शन नजर नही आए।मैं इतनी ही अपील करना चाहता हूं कि इसको जल्दी बाजी में किया गया हैं और जल्दी बाजी में किया हुआ निर्णय, कभी-कभी बड़े प्रायश्चित और पश्चाताप का कारण, अफसोस का कारण बन जाता हैं। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह हैं कि जो आपने कदम बढ़ाया हैं, यह जल्दी बाजी में लिया हुआ कदम हैं और बड़े पैमाने पर इस पर बहस कराकर तमाम पाठ्य-पुस्तकों में परिवर्तन करने की बात की तो आपके कदम को वास्तविक कहा जा सकता हें उचित कहा जा सकता हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शंकर राय चौधरी (पश्चिमी बंगाल): माननीय उपसभापति महोदय, आज की जो बहस हैं, मैं इसमें अपनी कुछ परेशनिंशया या सवाल रखना चाहता हूं। मैं अपनी चर्चा के दौरान यह कोशिश करूंगा कि इसमें न हिन्दुतव का जिक्र हो और न ही धर्म निरपेक्षता का जिक्र हो। लेकिन मैं यहां कुछ सवाल रखना चाहूंगा क्योंकि जो आज की चर्चा का विषय हैं, यह स्कूल टेक्स्ट बुक की बदली करने में छात्रों को जो परेशानी होती हैं, उसके बारे में कुछ-कुछ कहने के बारे में हैं। मैं पहला यह सवाल करना चाहूंगा कि जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो हमारी सरकारें हैं, ये हर पांच साल में या उससे ज्यादा समय में बदलती रहेगी तो मेरा सवाल यह हैं कि क्या जब नई सरकार आएगी तो बार-बार नई टेक्स्ट बुक्स लिखी जाएंगी? आज जो हमारे छात्र हैं, क्या यह समस्या उनको परेशान नहीं कर रही हैं? आज पूरे शिक्षा के माहौल में एक अस्थिरता आ गई हैं। पिछली दफा जब शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था तो उसमें कुछ स्टेट के मंत्रियों ने सरस्वती वंदना की बात पर बहिष्कार किया था। इस दफा देखा हैं कि जब राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलप हुआ था उसमे जो लफ्ज इस्तेमाल होता हैं, मुझे खुद पंसद नहीं हैं, भगवाकरण के मुद्धे पर कई शिक्षा मंत्रियों ने उसका बहिष्कार किया था। मेरा सवाल यह हैं कि यह जो अस्थिरता हैं, यह कब तक चलती रहेगी? दूसरा सवाल मुझे यह पूछना हैं कि हमारा जो इतिहास हैं, क्या वह सही इतिहास हैं? जो सवाल मैने पहले किया था, हर सरकार के साथ, हर पोलिटकल पार्टी के साथ, क्या हमारा अपने इतिहास के प्रति जो दृष्टिकोण हैं, वह बदलना पड़ेगा? सबसे बड़ी कमजोरी, जो मैं हमारी इतिहास की शिक्षा में समझता हूं, वह यह हैं कि जब हम लोग स्कूल में जाते थे, तब उस वक्त हिंदू पीरियड,मुस्लिम पीरयिड का इतिहास पढ़ाया जाता था, मैं आजादी से पहले की बात कर रहा हूं। अभी जो इतिहास पढ़ाया जा रहा हैं, उसमें कुछ-कुछ तब्दीली हुई हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो अभी आजाद हिंदुसतान हुआ हैं, 1947 के बाद आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में जो उतार-चढ़ाव होते आए हैं, जो-जो घटनाएं घटी हैं, जो-जो मुसीबते हमें झेलनी पड़ी हैं, हमने उनका मुकाबला किया हैं। 1947 के बाद का इतिहास अभी तक इतने जोर से नहीं पढ़ाया जा रहा हैं, उसके ऊपर उतना अटेशन फोकस नहीं किया जा रहा हैं, जितना होना चाहिए। आज अगर आप किसी छात्र से सवाल करे, जैसे आपने अभी जयप्रकाश नारायण जी का जिक्र किया था, मेरे ख्याल से अगर आप, अपने छात्रो से जयप्रकाश जी के बारे में पूछे तो उन्हें जयप्रकाश जी के बारे में कम ही जानकारी होगी। इसलिए मेरा यह कहना हैं कि जैसे भी हम इतिहास को लिखते हैं, हमें यह चाहिए कि सन् 1947 के बाद का आजाद हिंदुस्तान, जो एक नया हिंदुस्तान, जो एक नया हिंदुस्तान बना हैं, इसके इतिहास के ऊपर और बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए। हमारी टैक्स्ट बुक्स मे, जो मैं देखता हूं, उनमें इतना जोर नहीं दिया गया हैं, कुछ लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। अभी जो हालाम हैं, जो माहौल हैं, इसमें जरूर एक बदलाव आया हैं। मेरे अपने ख्याल से यह बदलाव उस वक्त से आया हैं, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई।

उसके बाद में एक माहौल बदल गया। पहले यह माहौल नहीं था, पहले ऐसा माहौल नहीं था। आजकल हर बात पर जो एक अस्थिरता हैं, वह हर बात पर, हर सवाल पर खड़ी होती हैं। अभी जो इतिहासकार हैं, जिसे भी आप लगाइए, चाहे वे कितने बड़े, कितने माने हुए इतिहासकार हों, उन पर किसी न किसी तरफ से आपत्ति आती रहती हैं। हमारे सामने मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश का सही इतिहास, खास तौर से आजादी के बाद का जो इतिहास हैं, उस पर जोर लगाकर, अच्छे इतिहासकारों को बुलाकर, यह होना चाहिए कि आजाद हिंदुस्तान ने जिस तरीके से आगे बढ़ोतरी की हैं और आजादी के इन मौकों पर हमारे जो कारनामें हैं, उन कारनामों पर जोर देकर हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि आगे चलकर उन्हें यह पता हो कि हमारा देश कितना शाक्तिशाली देश हैं। हम लोगों ने, हमारी जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया हैं, कैसे हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे नेताओं ने काम किया हैं। बात चली हैं राजनीतिकरण की। राजनीतिकरण होता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं हैं। इससे हम अलग नहीं हो सकता हैं, लेकिन हमें कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा हक चाहे सरकार बदले, चाहे पोलिटिकल पार्टी बदले, लेकिन हम जो अपने बच्चों को भविष्य के लिए पढ़ाने हैं, वह हमारे मुल्क का एक सही इतिहास, सही ढंग से और ठीक तरीके से उसे पढ़ाया जाए।

अंत में, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। हमारे दक्षिण से आए मित्र ने अभी तमिल में बोला। मैंने उन का ट्रांसलेशन सुना हैं। वह ठीक कह रहे थे कि हमारे जितने इतिहास लिखे गए हैं,उनमें दक्षिण भारत और पूर्व भारत का अधिक जिक्र नहीं होता हैं जबकि जो हमारा इतिहास लिखा जाए, उसमे हमारे हिंदुस्तान के हर रीजन के इतिहास को पूरी जगह मिलनी चाहिए। दूसरी बात, यह मेरा अपना विचार हैं कि जिसे सेफ्रोनाइजेशन कहते हैं, मेरे ख्याल से यह लफ्ज गलत हैं। महोदय,सेफॉन या भगवा हमारे देश के झंडे का हिस्सा हैं, इसे किसी पिजोरेटिव टर्म्स मे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे बताने के लिए अगर कोई लफ्ज इस्तेमाल करना पड़े तो कोई और लफ्ज आप निकालें क्योंकि यह लफ्ज गलत हैं। मैं इसे गलत मानता हूं।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : If they distort history, then, what do we call it?

श्री शंकर राय चौधरी : मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे देश में सन् 1947 के बाद जो घटनाएं घटी हैं, उन के बारे में हमारे बच्चों को जितनी जानकारी होनी चाहिए, वह नहीं हैं। उस ओर दिया जाना चाहिए। वहीं हमारा इतिहास हैं। उस से पहले का इतिहस भी हमारा इतिहास हैं, लेकिन जो आजाद हिंदुस्तान का इतिहास हैं, उस पर ज्यादा जोर दिया जाए। हिंदुस्तान के हर इलाके में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन को इतिहास में स्थान मिलना चाहिए जो मेरे ख्याल में अभी तक नहीं मिला हैं। अंत मे, दोबारा कह रहा हूं कि यह जो "सेफ्रन" लफ्ज हम बार-बार इस्तेमाल करते हैं, उस को मेरे ख्याल से बुरा दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस के लिए कोई और लफ्ज ढूंढा जाए।

श्री उपसभापति : श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे। देखिए,आप की पार्टी का पूरा समय हो गया हैं, थोड़े समय में अपनी बात कह दीजिए।

SHRI BALAWANT alias BAL APTE : Sir, I am aware of it, and I am grateful to you for giving me the opportunity to participate in this debate.

....(व्यवधान).... Sir, I am not worried about the word 'saffron' because it will survive in spite of all of them.

I was reading the title of today's 'List of Business' which says, 'the situation arising due to changes in the school text books by the Central Government'. So, you use English as a medium or as a subject, we will use this kind of English itself at the highest level.

Sir, we are discussing the effects of a Government Order of the Ministry of Human Resource Development passed on 12th June, 2004. Probably, everybody is aware that 12th June is a catastrophic date for this country. That was the date when 29 years ago, the then Prime Minister was unseated by a court order and what followed was the darkest period of our democracy. Same catastrophe awaits us because of this Order of 12th June, 2004. At that time, during Emergency, the history was moulded according to the choice of the rulers, which was sought to be encapsulated and was buried deep so that generations thereafter would understand the history as they wanted them to understand. Similar sinister effort is sought to be made again by this 12th June, 2004 Order. *...(Interruptions)...* Yes, yes, there was a capsule which was buried, which was taken out, and that capsule contained pervert history.

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh) : Please yield for a minute. *...(Interruptions)...* Let him decide whether he wants to yield or not; otherwise, it is all right, and I will sit.

SHRI BALAWANT *alias* BAL APTE: We are already late.

SHRI ANAND SHARMA: I will just take half-a-minute. You have made a reference.

SHRI BALAWANT *alias* BAL APTE: If I yield, I will have to reply and my response will get longer, and the Deputy Chairman will have to permit me. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him speak...*(Interruptions)...*

SHRI ANAND SHARMA: I deeply appreciate that; at least, he has yielded. He has made a reference to a capsule being buried to distort history during the Emergency, which is not correct. After Emergency was over, there was a Commission which was set up by the then Education Minister in the Janata Party Government and he stood for days and weeks with an umbrella in hand - you take out the records - trying to find the

7.00 p.m.

capsule. The capsule was dug out and they could not find a single objectionable thing. It is just one thing which I am correcting. Dr. Murli Manohar Joshiji is here. If they say anything objectionable, only they know and the rest of the country is in dark.

SHRI BALAWANT alias BAL APTE: The fact remains that a capsule Was buried. A capsule, according to them, included history of their choice. The Emergency was not over. The Emergency regime was overthrown by the people. They were thrown out of power. Evil was buried and the capsule was taken out. *...(interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY: Were you not thrown out of power because you distorted history? *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, please. *...(Interruptions)...*

SHRI BALAVANT alias BAL APTE: I am ready to yield to some logical argument. *...(Interruptions)...* I am not yielding. *...(Interruptions)...* I do not yield to noise; I yield to logic. Therefore, I am not yielding to you. *...(Interruptions)...* By this catastrophic order, eminent historians are sought to be appointed to review the text books. But this review is guided. These historians have no choice. What the historians have been told is that they should consider the text books and what their recommendations should be. So, the historians are appointed. Their recommendations are enumerated in the order of appointing them and as to what they should recommend, 'you are appointed, you say this.' Their recommendations should be 'for removing distorted and communally biased portions and for including short passages, which will fill in the gaps which some of these books, are supposed to be having.' So, the order is vitiated by pre-judgement, prejudice and ideological myopia. Experts are appointed. It is an idle exercise because what the experts should recommend is already said here. So, there are portions, which are distorted and communally-biased, and I tell you what they are and then you recommend to me that you remove them. This is not the way the experts are asked to work. This is the way experts are used. Here some experts have permitted themselves to be used by selling their intellect. I really do not consider them experts because of this. So, this order, as I said, is a matter of pre-judgement, is a matter of prejudice and it suffers from ideological myopia. The text books are already there in the field. During the last two years, six crores of copies of

these text books have been sold. They are applied and used in most of the States, including Congress led State Governments. They are used by the teachers with great satisfaction and the demand for them is growing every day. This is a matter of record, which should be understood before an undue and unholy haste is made for withdrawing all these popular text books. Now I come to the question of communalisation of curricula of these textbooks. Some of the friends of the hon. Minister, when he was not in office, tried to go to the Supreme Court, filed a writ petition and that writ petition, the very questions, which are being touted now, were raised. I would like to point out two questions, which were expressly argued before the Supreme Court.

One is, 'the respondents, that is the Government have not sought the approval of the Central Advisory Board of Education to the national curriculum framework for school education and without obtaining the approval of CABE, *i.e.*, Central Advisory Board of Education, NCFSE cannot be implemented. That is one point. NCFSC cannot be implemented. Secondly, 'NCSFE, that is the National Curriculum and the Syllabi framed there under are unconstitutional as the same are violative of the rubric of secularism, which is part of the basic structure of our Constitution.' Both thest- questions were answered with a resounding 'no' by the Supreme Court. So, what is being done today in the name of secularism is inconsistent with what the Supreme Court has said. Supreme Court has unanimously said, "The rubric of secularism is not disturbed by the new curriculum produced by the NCERT". Probably they want the Supreme Court orders to justify their secularism when it is convenient, but they want to ignore the Supreme Court orders when it is not convenient to their kind of secularism. I believe this is not the way you function as a Government, this is not the way you function politically.

There is one more aspect and it is the procedure that has to be adopted by the NCERT. During this session, a question was put to the hon. Minister with the hope that he will enlighten us on what the procedure to be adopted by the NCERT should be. The specific question was: 'whether it is a fact that NCERT text books are studied exclusively by students in the CBSE affiliated schools? What procedure is laid down and followed in carrying out such revisions on each occasion.' There is a lengthy reply but this reply does not mention the procedure that is sought to be or that is required to be followed by the NCERT. The only sentence in respect of procedure concerned is, 'It seeks to ensure all processes are

duly followed which were undermined during the last few years'. What processes? . The reply is blissfully silent because probably the Minister was not aware what that procedure was. But the procedure which I have is: there were 20 steps which were taken by the NCERT for interaction with experts, interaction with parents, interaction with educationists and interaction with State Governments. Seminars at all levels were held, meetings with Education Ministers were held, meetings with Chief Ministers were held, communications are there, and naturally it is not convenient and therefore, it is not considered. Then, there is one word about experts. Sir,-in this country an art is developed by those of the persuasion of the Left, calling each other experts and then inviting each other and reviewing each other's books and creating an aura of a peer group of experts and then inviting each other. They, then, call themselves as eminent historians. Now, fortunately, because of some research, 'eminent historian' has become a term of art in this country because everybody is reminded by those words about the book by Shri Arun Shourie which spoke about the work of these eminent historians, and they spent the treasury's money without producing results. Everybody is reminded of this by the use of two words only, 'eminent historians'. Therefore, those eminent historians are again being brought into the picture so as to write a new kind of history.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Kindly conclude. Mr. Apte, please conclude now.

SHRI BALAVANT *AUAS* BAL APTE : Yes, Sir. I am concluding. What I am disturbed about is, this attempt - I don't know whether I can use the word, 'secularisation' - is not an isolated one. This is one in a chain adopted by the present dispensation and it is reflected in various ways. Somebody, while blaming the former HRD Minister, talked about the Two-Nation theory. And the symbol of the Two-Nation theory is, today, part of the Union Cabinet. Therefore, I say that this is not an isolated instance. This is a part of a great series which indicates the pre-partition syndrome and creates a similar threat as was created on 12th June, 1975.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI BALAWANT *AUAS* BAL APTE: Sir, we have the incident of Ishrat Jahan. We have the POTA. We have the Muslim League participating. Therefore, I believe that this kind of mentality will divide the country, will divide the society, will divide the polity. Therefore, this division

has to be stopped, this attempt has to be stopped by the people with all their might. Thank you.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM (Tamil Nadu): Thank you very much, Mr. Deputy Chairman, Sir, for the opportunity given to me to speak on this subject. I consider it as the greatest sin to twist the history and is still greater a sin and injustice to leave out and erase any portion or any due contribution of a particular society from the history books. The panel of historians - Mr. S. Settar, Mr. J.S. Grewal and Mr. Barun De - submitted a Report to the Ministry of HRD in July, 2004. It is painful to note that in Appendix 1A, at page 12, it says that about 1,050 schools in the country are compelled to teach wrong history of this nation. Of these 1,050 schools, 150 schools are in Tamil Nadu alone which are following the CBSE system of education. These schools, it is really painful to learn, are teaching wrong history and twisted history. As per the Report, there is a lopsided treatment of the ancient history of India. The Report says that the ancient India is identified with Indo-Gangetic zone. The events of the rest of the country, the entire peninsula, North-East and parts of the extreme East are more or less viewed as of no relevance by those who prepared this syllabus. This is borne out also from the fact that out of 89 pages devoted to the study of ancient history, not even 9 full pages are spared for the history of the peninsular India.

In the Southern part of India, which has got the ancient history and very rich culture - this is evident from the Report that over 50,000 inscriptions have been found. They speak volumes of history of the Southern part of India. At page 10 of Appendix IA the Report says about the wrong statement of the inscription stone, which is called as Nadukal, and a different name has been given to it. The Nadukal, as per the ancient Tamil literature, is a stone installed in a particular place depicting the valour of a particular king or a soldier and it contains the contemporary records of the happenings in a particular area and a lot of such inscriptions were found and there is a wrong statement on this is really painful.

At the same page, it has also been reported that the period of Chola Kingdom and their achievements have been wrongly stated. The Chola kings of Tamil Nadu, the history says, had conquered the South-East Asian countries. We have inscriptions at places like, Java and Sumatra, which were, at some point of time, ruled by Cholas. That has also been wrongly stated. Then, in paragraph 4 of the Report, it has also been mentioned that some facts about the Sangam Literature and their method of

selection have wrongly been stated. The Sangam Literature of Tamil language had been in practice for over 2000 years. There were poet laureates and literary geniuses in the royal court. The literary works, at that time, used to be selected through a special method. They were recognised. In fact, they were given a greater recognition. The literature, like, Purananooru and Agananooru, which contained 400 poems each, have the treasure of knowledge about literature and history. Further, there are historical accounts which show that the ancient Tamil kings, like Pandya, had ambassadorial relationship in Europe. All this is evident from historical records present, both in the European history and the Tamil history. The British came to India in late 17th century. And about 200-300 years prior to that, the Dutch came. And, prior to seventh century some Chinese travellers visited India. All of them had recorded the history of the Southern part of India. It is painful that none of them have been referred in the text books which are being taught. Sir, here, I would like to make a particular reference to one of the books, written by one, Shri A.C. Gover, a Britisher, who was here nearly two centuries ago. He had written a book 'Folk Songs of Southern India', which had been submitted to the Royal Asiatic Society, London. In this book, he had a lot of details to speak about the ancient Tamil history, particularly about the Thirukkural. All of them have been omitted. Even in the modern history, it is painful to see, the contributions made by Subramanaya Bharati, one of the great poets, one of the leading freedom movement personalities in the Southern part of India, have been omitted. With these words, I conclude, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The general discussion on the Short Duration Discussion is over. Hon. Minister of Human Resource Development will reply to the debate tomorrow. The House, now, stands adjourn till 11.00 a.m. tomorrow, the 19th August, 2004.

The House then adjourned at fourteen minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 19th August, 2004.